मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | ग्वालियर, रविवार 25 अक्टूबर 2026 | वर्ष-08, अंक-194, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री ने धार में 2387.60 करोड़ रुपए लागत की नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश में सिंचाई का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। प्रदेश में सरदार सरोवर बांध के बाद अलग-अलग परियोजनाओं के माध्यम से धार-झाबुआ क्षेत्र को पर्याप्त जल उपलब्ध हो रहा है। क्षेत्र के किसानों को 2387.60 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की सौगात मिली है।



प्रदेश में वर्ष 2002-03 तक केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। सिंचाई का रकबा वर्ष 2023 तक सिंचाई रकबा बढ़कर 40 लाख हैक्टेयर हो गया। अब पिछले ढाई साल में हमारी सरकार ने सिंचाई का रकबा 60 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाया है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। सूखे खेतों को जब पानी मिलता है तो किसानों की फसल सोने जैसे चमकने लगती है। राज्य सरकार कृषि, उद्योग सहित प्रत्येक सेक्टर में काम कर रही है। प्रदेश के किसानों की समृद्धि ही हमारा ध्येय है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में अनेक कार्य हुए हैं। आज प्रदेश के 16 लाख 70 हजार किसानों को दीवाली त्यौहार से पहले 317.86 करोड़ की राशि भेजकर सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई सुविधाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब धार को भी रेलवे लाइन की सौगात मिल चुकी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार में अपने जन्मदिन पर पीएम मित्र पार्क की बड़ी सौगात दी। इस परियोजना से निमाड़-मालवा क्षेत्र के लगभग 6 लाख कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। अब एक ही स्थान पर कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स तैयार किए जाएंगे। यहां के धागे से निर्मित वस्त्रों का निर्यात भी होगा। प्रदेश के 3 लाख लोगों को पीएम मित्र पार्क से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब धार-झाबुआ के युवा, किसान और महिलाएं पलायन को विवश नहीं होंगे। नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से दोनों जिलों के 260 गांवों की 57,422 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और करीब 72 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

लोकार्पित परियोजना एक नजर में

नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के तहत मॉ नर्मदा का जल माही नदी में छोड़ा जाएगा। परियोजना अंतर्गत धार जिले में 66 ग्रामों में 25 हजार 422 हैक्टर भूमि एवं झाबुआ जिले के 194 ग्रामों के 32 हजार हैक्टर भूमि में सिचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त परियोजना से लगभग 72 हजार कृषक लाभांवित होगे। परियोजना से झाबुआ जिले की झाबुआ तहसील के 108 ग्रामों की 17802 हेक्टेयर, पेटलावद तहसील के 06 ग्रामों की 1502 हेक्टेयर, मेघनगर तहसील के 28 ग्रामों की 5504 हेक्टेयर, थांदला तहसील के 39 ग्रामों की 5927 हेक्टेयर, रामा तहसील के 12 ग्रामों की 1185 हेक्टेयर, राणापुर तहसील के 01 ग्रामों की 80 हेक्टेयर, एवं धार जिले की सरदारपुर तहसील के 66 ग्राम में 25422 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 260 ग्रामों के कृषकों को 57422 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा। परियोजना अंतर्गत ग्राम चन्दनखेड़ी तहसील कुक्षी में नर्मदा नदी से 186.62 एमसीएम जल का उ ?द्वहन किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना में 102.30 मेगावाट बिजली की खपत होगी।

फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान-साहिल

एजेन्सी, **मेरठ**



मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने मेरठ की जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की है। अदालत ने 14 अक्तूबर को दोनों को मौत की सजा सुनाई थी। अब दोनों चाहते हैं कि हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को रद्द करे।

यह मामला मर्चेंट नेवी कर्मी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। मार्च 2025 में सौरभ की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और फिर फांसी की सजा सुनाई। मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर, 2026 को मुस्कान और साहिल को हत्या करने और सबूत छिपाने के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 14 अक्तूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब हाई कोर्ट में दाखिल अपील में दोनों ने सिर्फ मौत की सजा ही नहीं, बल्कि दोषी ठहराए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।

मक्का-मदीना में मिसाइलों के टुकड़े गिरने की चेतावनी

हूतियों ने सऊदी के तेल ठिकानों-एयरपोर्ट्स पर हमला किया

एजेन्सी, **सऊदी अरब**

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब के तेल ठिकानों और एयरपोर्ट्स पर हमला किया है। हूती प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक, निशाने पर सऊदी तेल कंपनी अरामको का यानबू ठिकाना, राबिग तेल रिफाइनरी और रियाद, दम्माम व नजरान के एयरपोर्ट थे।

सऊदी सिविल डिफेंस ने मक्का और मदीना में मिसाइलों के टुकड़े गिरने की चेतावनी दी है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने को कहा गया है। इस महीने सऊदी अरब पर हूतियों ने 6 बड़े हमले किए हैं। हूती प्रवक्ता याह्या सरी के मुताबिक



उनकी सेना ने अदन में सैन्य कैंप और नौसैनिक अड्डे को भी निशाना बनाया।

अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का अंतरिम केंद्र है। यहां हाल के दिनों में भी हमले हुए हैं। 15 अक्टूबर को अदन में राष्ट्रपति भवन परिसर पर मिसाइल हमला हुआ था। यमनी अधिकारियों के मुताबिक, इसमें पांच लोगों की मौत हुई और 16 घायल हुए। प्रधानमंत्री शाया अल-जिंदानी और सरकार के दूसरे अधिकारी सुरक्षित रहे।

16 अक्टूबर को अदन एयरपोर्ट परिसर में भी दो मिसाइलें गिरी थीं। यमनी अधिकारियों के मुताबिक, ये मिसाइलें काहिरा जाने के लिए तैयार एक यात्री विमान से करीब 500 मीटर दूर गिरीं। इस घटना में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं थी। यमन की सरकारी सेना ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा हमले किए हैं।

Jio IPO के 3 दिन में 7 रिकॉर्ड

देश का सबसे बड़ा इश्यू, 100 मिनट में पूरा भरा, टारगेट से 22 गुना ज्यादा बोलियां



एजेन्सी, **मुंबई**

5 सितंबर 2016, रिलायंस ने जियो नाम से फ्री सिम बांटनी शुरू कीं। इतना ही नहीं, अगले 6 महीने इंटरनेट भी मुफ्त दिया। जियो स्टोर्स पर ग्राहकों की लाइन लग गई। दस साल बाद यही जियो जब भारत का सबसे बड़ा IPO लाई, तो लोग एक बार फिर टूट पड़े। जियो दुनियाभर में 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन पाने वाला पहला IPO तो बना ही, इसने 3 दिन में 7 रिकॉर्ड बना डाले।

ग्लोबल स्टॉक मार्केट के इतिहास में जियो प्लेटफॉर्म्स पहला ऐसा IPO बन गया है, जिसे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर एप्लीकेशन मिले हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत की ही वारी एनर्जीज के नाम था, जिसे लगभग 97.3 लाख आवेदन मिले थे। 30,213 करोड़ के इश्यू साइज के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स का क्वड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इक्विटी ऑफरिंग बन गया है। इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था।

एंकर बुक समेत जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के लिए कुल शेयर डिमांड 7.4 लाख करोड़ रही। पब्लिक सब्सक्रिप्शन कैटेगरी से ?4.9 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिलीं। डेटा के आधार पर एंकर बुक के बाहर मिली बोलियों की वैल्यू के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा क्वड बन गया है, जिसने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2025 IPO के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

सतना-देवेंद्रनगर एवं रीवा-चुरहट रेलखंड देश को समर्पित

विंध्य एवं बुंदेलखंड आए करीब, सीधी जिले को बड़ा लाभ, रेल मंत्री व सीएम यादव ने किया शुभारंभ

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में सतना-देवेंद्रनगर एवं रीवा-चुरहट नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर देवेंद्रनगर-चुरहट नई यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

चुरहट रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा के सांसद श्री जनार्दन मिश्रा,



सीधी के सांसद श्री राजेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नागौद रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, सतना के सांसद श्री गणेश सिंह, खजुराहो के सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में एक नई जीवनरेखा स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी तथा क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाएगी। श्री वैष्णव ने देशभर में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार का उल्लेख करते हुए श्रीनगर, मिजोरम और पंबन ब्रिज में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में रावघाट और मध्य प्रदेश में टांडा रोड को हाल ही में रेल नेटवर्क से जोड़ने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया।

ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत देवेंद्रनगर-सतना और रीवा-चुरहट रेलखंडों पर रेल परिचालन शुरू होने से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

भाजपा और विहिप ने कांग्रेस को घेरा

हैदराबाद में भगवान राम की प्रतिमा हटाने पर विवाद

एजेन्सी, **हैदराबाद**

हैदराबाद में शनिवार को एक मंदिर से भगवान राम की बड़ी प्रतिमा हटाए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस कदम को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

दशहरे के दौरान बशीरबाग स्थित देवी कनक दुर्गा मंदिर में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय विहिप के नेताओं ने घोषणा की थी कि इस इलाके को बशीरबाग नहीं, बल्कि श्रीराम चौक के नाम से जाना जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शनिवार को मंदिर की प्रबंधन समिति ने प्रतिमा हटा दी। सूत्रों ने बताया कि दशहरे का उत्सव समाप्त होने के बाद प्रतिमा को हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष



एन रामचंदर राव ने कहा कि लोग प्रतिमा हटाने के मामले में न तो कांग्रेस सरकार को भूलेंगे और न ही माफ करेंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस सरकार ने भगवान राम की प्रतिमा हटाने की कोशिश की है। वर्ष 1949 में अयोध्या में रामलला की प्रतिमा प्रकट होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर उसे हटाने का दबाव बनाया था। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो चुका है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ आह्वान पर भोपाल में 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने भरी हुंकार

लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन बैलेट से होता है, भीड़तंत्र से नहीं : सोलंकी

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत शनिवार को भोपाल के अटल पथ, टीटी नगर में रैली निकालकर विद्यार्थी हुंकार प्रदर्शन किया। 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों और अभाविप के पदाधिकारियों-कार्यकताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि राष्ट्रवादी विचार के युवाओं की ताकत अराजकता करने वालों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 से पहले मध्यप्रदेश दुव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। स्कूल-कॉलेज में पढ़ते समय रात का होमवर्क शाम को करने के लिए चिमनी में पढ़ना पड़ता था। कई दिनों तक बिजली नहीं मिलती थी। आज वही मध्यप्रदेश विकसित प्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह राष्ट्रवादी



विचार के युवाओं की ताकत ही है कि राम विरोधी, राम मंदिर विरोधी, सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से कथित रूप से संलिप्तता रखने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आज सनातन यात्रा करनी पड़ रही है। संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लाने तथा अराजकता के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के प्रयास स्वीकार्य नहीं हैं। निर्वाचन प्रक्रिया अथवा किसी भी संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित शिकायतों का समाधान संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री श्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि षड्यंत्रकारी भारत को अराजकता की ओर ढकेलना चाह रहे हैं। देश का युवा समझदार है वह देश विरोधी व अराजकता फैलाने वालों के साथ कभी खड़ा नहीं होगा।

हमारे राष्ट्र का युवा कभी अपने देश को बांग्लादेश नहीं बनने देगा : डॉ. वीरेन्द सोलंकी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि नेहा बोरा का जेएनयू में पढ़ते-पढ़ते इतना ब्रेनवॉश किया गया कि अपने देश के खिलाफ ही बोल रही हैं। नेहा बोरा कह रही हैं कि बांग्लादेश से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का कोई भी युवा नेहा बोरा की तरह नहीं सोचता। भारत का युवा राष्ट्र भक्त है और अपने देश के साथ पूरी ताकत और तटस्थता के साथ खड़ा है। भारत का युवा अपने देश को कभी बांग्लादेश नहीं बनने देगा। भारत को बांग्लादेश बनाने वालों के मंसूबों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि नेहा बोरा ने अपने पिता से 10 साल तक बात नहीं की।

भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास और संवैधानिक स्वतंत्रता पर आधारित है

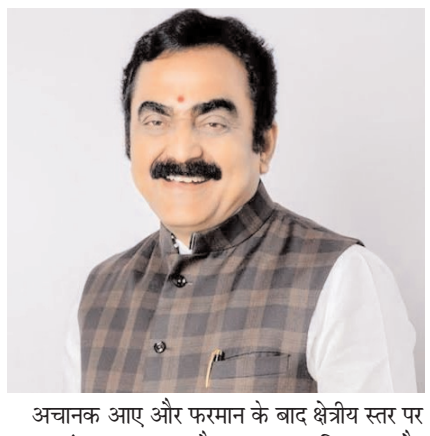
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास, मताधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका समाधान संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत ही होना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अभाविप सदैव विद्यार्थियों के बीच राष्ट्र प्रथम की भावना, लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करती रही है।

दिल्ली दरबार में बढ़ी महाकोशल की धमक

मप्र की राजनीति में राकेश सिंह को लेकर अटकलें तेज, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन द्वारा गठित की जा रही 'स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन समिति' में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री राकेश सिंह को एक अहम और बड़ा राष्ट्रीय पद सौंपे जाने की प्रबल संभावना है। पार्टी के भीतरखाने से आ रही खबरों के मुताबिक, मध्य प्रदेश से इस पद के लिए दो नाम विचाराधीन थे, लेकिन राकेश सिंह की सांगठनिक दक्षता और प्रशासनिक कार्यकुशलता के चलते केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा उनकी झोली में जाता दिख रहा है। इसे उनके राजनीतिक कद में एक सीधी और बड़ी पदोन्नति के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच, शनिवार 24 अक्टूबर को दिल्ली में एक अति महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मंत्री राकेश सिंह दोपहर 12 बजे जबलपुर से प्रस्थान कर सबसे पहले भोपाल पहुंचे और वहां से विमान के जरिए सीधे नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय स्तर पर मिलने जा रहे इस संभावित और कद्दावर दायित्व को न केवल जबलपुर बल्कि समूचे महाकोशल और मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अचानक बदले प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरण शीर्ष नेतृत्व के इस



अचानक आए और फरमान के बाद क्षेत्रीय स्तर पर हड़कंप सा मच गया है। जनसमस्या निवारण और विकास कार्यों के शिलान्यास से जुड़ी सभी पूर्व निर्धारित प्रशासनिक बैठकों को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया है। अचानक बने इस दौरे के कारण सरकारी अमले और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भेड़ाघाट में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नर्मदा महोत्सव में इस बार परंपरा टूटती नजर आएगी। इतिहास में यह पहला मौका होगा जब इस सांस्कृतिक जल समारोह में कोई कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहेगा। मंत्री राकेश सिंह की इस कार्यक्रम से दूरी ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

महाकोशल में उभरे नए राजनीतिक गणित

शीर्ष नेतृत्व के अचानक आए फरमान के बाद क्षेत्रीय स्तर पर जनसमस्या निवारण एवं विकास कार्यों के शिलान्यास से जुड़ी सभी पूर्व निर्धारित प्रशासनिक बैठकें आगे बढ़ा दी गई हैं। इस अप्रत्याशित यात्रा कार्यक्रम के कारण सरकारी अमले और पार्टी कार्यकर्ताओं की तैयारियों पर एकाएक रोक लग गई है शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नर्मदा महोत्सव में पहली बार कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं रहेंगे। इस सांस्कृतिक जल समारोह से दूरी बनने के बाद अब सभी की नजरें दिल्ली में प्रस्तावित गोपनीय मंथन पर टिकी हैं, जिससे प्रांतीय सियासत में नए समीकरण आकार लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई जा रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन समिति में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को अहम पद सौंपे जाने की प्रबल संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य से विचाराधीन 2 नामों में राकेश सिंह की कार्यकुशलता के चलते केंद्रीय नेतृत्व उन पर गहरा भरोसा जता रहा है, जिसे उनके राजनीतिक कद में सीधी पदोन्नति माना जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार 24 अक्टूबर को आयोजित अति महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने के लिए वे दोपहर 12 बजे जबलपुर से प्रस्थान कर पहले भोपाल पहुंचेंगे और फिर वहां से विमान मार्ग द्वारा सीधे नई दिल्ली रवाना होंगे।

तकनीक से कसेगा फील्ड का हर ढीला पेंच

शहर की व्यवस्था सुधारने की तैयारी, स्मार्ट कैमरों से होगी ट्रैफिक और सफाई की निगरानी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

दमोह नाका स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का औचक निरीक्षण करते हुए नगर निगम आयुक्त अग्रिम कुमार ने तकनीकी निगरानी, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जनसुविधाओं को बेहतर करने के कड़े निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 3 दिनों में प्रत्येक वार्ड की डेटा आधारित समीक्षा रिपोर्ट तलब की। इस दौरान अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, उपायुक्त संभव अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा और तकनीकी अधिकारी बालेंदु शुक्ला मौजूद रहे। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि आधुनिक तंत्र केवल कागजी रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि जमीनी समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए है। स्वास्थ्य, जल और कर्मशाला विभाग को एकजुट होकर काम करने का आदेश देते हुए उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन, शिफ्ट व्यवस्था और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने पर सीधा बल दिया। दमोह नाका केंद्र पहुंचे निगमायुक्त ने ऑन-ड्यूटी



कंप्यूटर ऑपरेटरों से सीधा संवाद कर सॉफ्टवेयर संचालन और शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण की वास्तविक स्थिति परखी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग का प्राथमिक उद्देश्य मैदानी अमले की सक्रियता बढ़ाना और सार्वजनिक सेवाओं की गति तेज करना है। सभी कर्मचारियों के कार्य के घंटे और शिफ्ट का विभाजन स्पष्ट रूप से दर्ज रहेगा, जिससे किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर जवाबदेही तय की जा सके। इसके साथ ही आईटीएमएस के कैमरों से शहर की यातायात व्यवस्था, चौराहों के सिग्नल और सुरक्षा पहलुओं की निगरानी को पहले से अधिक मजबूत करने पर सहमति बनी। उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी रखने और ट्रैफिक जाम से जुड़ी दिक्कतों को फौरन हल करने की रणनीति बनाई गई।

कचरा ऊर्जा संयंत्र और फील्ड कार्यों की समीक्षा

कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं देखने के बाद नगर निगम प्रमुख ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का रुख किया। वहां संयंत्र की संचालन क्षमता, कचरा निस्तारण की गति और बिजली उत्पादन प्रक्रिया की पड़ताल की गई। अधिकारियों को हिदायत दी गई कि प्लांट की तकनीकी खामियां दूर कर कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। 3 दिनों के भीतर तैयार होने वाली वार्डवार रिपोर्ट के जरिए स्वच्छता और पेयजल सप्लाई की कमियों को चिह्नित कर सीधे फील्ड स्तर पर समाधान निकाला जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य शाखा, पेयजल वितरण और कर्मशाला के वाहनों का आपसी तालमेल अनिवार्य किया गया है ताकि गाड़ियां समय पर कचरा उठाएं और पानी की टंकियां समय से भरें। तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा बैठकें होंगी, जिससे नागरिकों को सीधे जमीनी स्तर पर राहत मिल सके।

रेलवे स्टेशन के वाशिंग पिट पर अज्ञात अधेड़ की लाश मिली

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

रेलवे स्टेशन के वाशिंग पिट पुरानी डाउन केबिन के पास शुक्रवार की रात यार्ड में एक अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जीआरपी ने मृतक की अनुमानित उम्र 55 वर्ष बताई है। मामले की जाँच कर रहे प्रधान आरक्षक मोहम्मद शकील सिद्दीकी के अनुसार, रात करीब साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे यार्ड के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुँचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र की छानबीन की। पुलिस की शुरुआती जाँच में मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि इस अज्ञात व्यक्ति की मौत किसी गंभीर बीमारी के कारण हुई होगी। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल



अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी ने आसपास के सभी थानों में हुलिया भेज दिया है ताकि उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल आसपास के लोगों से पूछताछ कर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

'सुपरकॉप' की उड़नपरी ज़मीन पर, नो-एंट्री के साथ घर वापसी

एक सिपाही ने जारी किया पुलिस कप्तान को फरमान, मचा हड़कंप फिर एक्शन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

खाकी के महकमे में रौब की अपनी एक अलग ही भूख होती है, लेकिन जब एक अदना सा आरक्षक खुद को सूबे के तमाम पुलिस अधीक्षकों 'सुपर बॉस' समझ बैठे, तो किस्सा सिर्फ अनुशासनहीनता का नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रशासनिक हास्य का बन जाता है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ आरक्षक संदीप रघुवंशी ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया। साहब ने सरकारी लेटरहेड उठाया, महाधिवक्ता कार्यालय की मुहर का वज़न महसूस किया और एक झटके में मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के पुलिस कप्तानों को ईमेल दाग दिया। फरमान भी ऐसा-वैसा नहीं, बल्कि कड़क लहजे में सख्त ताकीद की कि दो दिन के भीतर अपने सीयूजी मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से



उपलब्ध कराएं!' सिपाही जी को गृह विभाग ने महज़ इसलिए भेजा था ताकि अदालती मामलों में विभागों के बीच 'हैलो-हाय' और कागज़ों की आवाजाही बनी रहे। मगर आरक्षक महोदय के भीतर का प्रशासनिक हुक्मरान शायद जाग चुका था। उन्होंने ज़िला कप्तानों को बाकायदा समझाया कि हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों, ज़मानत याचिकाओं, स्थानीय सत्यापन रिपोर्टों और नोटिस तामीली में तेज़ी लानी है। लगे हाथ पुलिस अधीक्षकों के रीडर और ज़िले की विधिक शाखा के प्रभारियों के नंबर भी मांग लिए, ताकि 'कामकाज में ढिलाई' न रहे। ज़िलों के पुलिस कप्तान भी एक पल को चौंक गए होंगे कि रातों-रात ऐसा कौन सा नया 'डीजीपी' महाधिवक्ता कार्यालय में बैठ गया, जो कप्तानों को 48 घंटे की मोहलत देकर फोन नंबर मांग रहा है। सिपाही ने समन्वय (कोऑर्डिनेशन) की जिम्मेदारी को सीधे नियंत्रण (कंट्रोल) समझ लिया और भाषा ऐसी चुनी, मानो गृह मंत्रालय का कोई कड़क फरमान जारी हुआ हो। जब यह 'शाही फरमान' महाधिवक्ता कार्यालय के आला अफसरों की नज़र में आया, तो वहां हड़कंप मच गया। जिस लेटरहेड की गरिमा का ध्यान बड़े-बड़े विधिक महारथी रखते हैं, उस पर एक आरक्षक सूबे की पुलिस को हांकने निकला था। इसे घोर कदाचरण, मनमानी और मर्यादा की सीमा लांघना करार देते हुए तुरंत चाबुक चला दिया गया।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत फंदे पर झूलने के बाद जमीन से घुटने



एक सत बुलेटिन, जबलपुर

पनागर से पांच किलोमीटर की दूरी पर जतवा गांव में एक बीस वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात वह घर पर अकेला था। सुबह आसपास के लोगों ने घर के पीछे से प्रवेश किया तो फंदा लगा जमीन में घुटने टेका युवक मिला, जो मृत हो चुका था। पुलिस ने शव पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पनागर टीआई विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि जतवा गांव में रहने वाले अभिषेक कोल ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। मृतक पेशे से मजदूर था। वह अपनी मां के साथ रहता था। उसके भाई-भाई घर के सामने अन्य मकान में रहते हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस ने पाया कि मृतक की मां शुक्रवार को मजदूरी करने गई थी। वह रात में अपनी बहन के घर में रूक गई थी। घर पर अभिषेक अकेला था। अभिषेक के बारे में पुलिस का कहना है कि वह नशे का आदि था। मृतक के शरीर के पास से नशे की बू आ रही थी।

लार्डगंज में शिक्षक का खाता साफ, मोबाइल चालू किया और खाते से कट गए 88 हजार

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

शहर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना लोग शातिर ठगों का शिकार बन रहे हैं। ताजा मामलों में रांझी और लार्डगंज थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग लोगों के मोबाइल फोन हैक कर उनके बैंक खातों से हजारों रुपये उड़ाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर साइबर सेल की मदद से तहकीकात शुरू कर दी है। लार्डगंज पुलिस थाने में यादव कॉलोनी निवासी शिक्षक शिवराज सिंह उइके ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि ग्यारह अक्टूबर को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे जैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन



किया, उनके मोबाइल पर गूगल पे के जरिए 88 हजार रुपये कटने का मैसेज आ गया। जब उन्होंने अपना बैंक खाता चेक किया, तो पता चला कि किसी अज्ञात ठग ने उनके खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए यह रकम अवैध रूप से ट्रांसफर कर ली है। इसी तरह रांझी इलाके में रहने वाले निशांत कुमार साहू ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। उनका कहना है कि अठारह अक्टूबर को उनका मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया और किसी रिमोट एक्सेस ऐप के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद उनके यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक के खातों से कुल एक लाख रुपये कटने के संदेश मिले। अज्ञात शातिर बदमाशों ने मोबाइल को अपने नियंत्रण में लेकर दोनों खातों से यह रकम ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी कर निकाली है।

बरेला टीआई संगीता सिंह के मुताबिक विवाद दोनों ओर से किया गया

बरेला के बम्हनी चौराहे पर भाजपा नेताओं में घमासान

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के बीच शुक्रवार की रात 9 बजे बम्हनी चौराहे पर जमकर विवाद हो गया। एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और हमला किया जाना सामने आया है। इस घटनाक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रवेश पटेल, प्रदीप साहू और दिलीप साहू सहित अन्य लोगों सहित महिलाओं के घायल होना सामने आया है। बरेला पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। बरेला टीआई संगीता सिंह के मुताबिक विवाद दोनों ओर से किया गया है। पुलिस जांच कर



रही है। इस प्रकरण में जनपद सदस्य रामेश्वर साहू जिला पंचायत सदस्य रानी साहू के पति बताए जा रहे हैं। उनके भाई प्रहलाद साहू, लखन साहू और दिनेश साहू सहित अन्य लोगों पर हमला करने के आरोप लगे हैं। वहीं, घायल बताए जा रहे लोगों में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष प्रवेश पटेल, प्रदीप साहू और दिलीप साहू के नाम सामने आए हैं। बरेला थाना प्रभारी ने बताया कि भाजपा नेता और उनके भाइयों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत सामने आई है। घायलों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राणघातक हमला और बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बरेला के पूर्व अध्यक्ष ने एसपी को दिया ज्ञापन और मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

अधिकारियों ने सिखाए सुरक्षा नियम एवं साइबर बचाव

थाने में कक्षा: सिविल लाइन पुलिस ने विद्यार्थियों को सिखाया नियम पालन का महत्व

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना प्रकोष्ठ द्वारा युवा सृजन संवाद के तहत आज सिविल लाइन थाने में एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। इस शैक्षणिक दल में योजना के संभागीय मार्गदर्शक प्रो. अरुण शुक्ल, प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. महेन्द्र कुशवाहा, डॉ. आनंद तिवारी, डॉ. तरुणेन्द्र साकेत तथा संस्थान के कुल 74 छात्र-छात्राएं शामिल रहे। सिविल लाइन थाना परिसर में थाना प्रभारी





शशि धुर्वे, मनीष दुबे, श्रद्धा गुर्जर, अनिल तिवारी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, दिलीप यादव एवं समस्त पुलिस स्टाफ ने अध्ययन दल का स्वागत किया। इस पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सुरक्षा तंत्र, कानूनी प्रक्रियाओं तथा खाकी की वास्तविक जिम्मेदारियों से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराना था। थाना परिसर में आयोजित संवाद सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को रोजमर्रा के कानूनी नियमों, सड़क पर चलने के लिए जरूरी यातायात अनुशासन, इंटरनेट पर होने वाली ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, महिला सुरक्षा के विशेष प्रावधानों तथा बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी पक्षों की बारीक जानकारी दी। उपस्थित स्टाफ ने युवाओं को संकट के समय त्वरित मदद पाने के लिए जारी आपातकालीन सहायता नंबरों के प्रयोग, सूचना दर्ज कराने की सही पद्धति तथा किसी भी अप्रिय घटना के समय तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के बारे में व्यावहारिक तौर पर समझाया। नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से बढ़ा सामाजिक दायित्व संवाद के दौरान विद्यार्थियों को यह समझाया गया कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने, अपराध नियंत्रण तथा जनसामान्य के मौलिक अधिकारों की हिफाजत में पुलिस विभाग किस तरह से निरंतर सेवारत रहता है। उपस्थित प्राध्यापकों ने इस पहल को युवाओं के भीतर कानूनी जागरूकता पैदा करने, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने और किताबों से बाहर निकलकर व्यवस्था को नजदीक से समझने की दिशा में एक अत्यंत उपयोगी कदम बताया। भ्रमण के समापन पर छात्र-छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा प्रक्रियाओं पर सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

न्यूज ब्रीफ

मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स से 57 कार्बाइड गन और विस्फोटक जब्त

ग्वालियर। दीपावली एवं अन्य उत्सवों के दौरान खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा उपयोग पर प्रतिबंध के पालन में जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जिलेभर में संयुक्त कार्रवाई की। ग्वालियर शहर में एसडीएम झांसी रोड अतुल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान सिरोल रोड, मुरार स्थित शिव नगर की मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स से 57 कार्बाइड गन और 5 पैकेट पोटाश जब्त किए गए। प्रशासन और पुलिस की टीम ने संबंधित दुकान को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान शहर के अन्य बाजारों में भी विभिन्न दलों ने छापामार जांच कर कार्बाइड गन और खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की उपलब्धता की पड़ताल की। इसी क्रम में भितरवार में भी एसडीएम राजीव समाधिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

संगीत व सम्मान समारोह आज, खास आयोजन को लेकर उत्साह

ग्वालियर। शरद पूर्णिमा की सुरमयी बेला में स्थानीय सांगीतिक संस्था 'रागायन' की ओर से पच्चीस अक्टूबर को एक दिवसीय भव्य संगीत व सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह गरिमामयी आयोजन ग्वालियर की समृद्ध संगीत विरासत को सींचने वाली दो महान विभूतियों–स्वर्गीय पंडित महीपत राव विष्णुपंत महाजनी और पंडित एकनाथ सारोलकर (दानी) की पावन स्मृति को समर्पित रहेगा।सिद्धपीठ श्री गंगादास जी की बड़ी शाला, लक्ष्मीबाई कॉलोनी में यह अनुष्ठान शाम छह बजे से आरंभ होगा। इस सांगीतिक संध्या में प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए सामवेद की ऋचाओं का दिव्य गायन किया जाएगा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ देकर कलाप्रेमी सुर-साधना की इस अनूठी परंपरा का उत्सव मनाएंगे।संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। शहर के संगीतप्रेमियों और कलाकारों के बीच यह आयोजन ग्वालियर के शास्त्रीय संगीत इतिहास को याद करने और उसे आगे बढ़ाने का एक अहम मंच बनेगा।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, युवा उत्सव के आवेदन 28 तक

ग्वालियर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद जयंती यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में पंद्रह से उन्नतीस वर्ष आयु वर्ग के युवा हिस्सा ले सकेंगे, जिसके लिए खेल विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।जिला खेल अधिकारी डॉ. अरविंद सिंह राणा ने जानकारी दी है कि जो भी इच्छुक आवेदक इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे अट्ठाइस जनवरी तक जिला खेल परिसर कंपू पर जाकर अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले युवाओं को ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि यह राष्ट्रीय युवा उत्सव मुख्य रूप से दो प्रमुख वर्गों–यंग लीडर्स और सांस्कृतिक ट्रैक के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं की नेतृत्व क्षमता और उनकी सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने व मंच प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

ब्लैक स्पॉट्स पर निगम की सख्ती, 04 कचरा प्वाइंट किए गए समाप्त

ग्वालियर। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लंबे समय से कचरा जमा होने वाले ब्लैक स्पॉट्स को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी एवं अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देशानुसार लंबे समय से कचरा जमा होने वाले ब्लैक स्पॉट्स साफ कराये जा रहे है जिसमें आज 4 ब्लैक स्पॉट्स साफ कराये गये। अब शकर में 71 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट्स है जिन्हें भी जल्द साफ किया जावेगा। मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा स्थलों को समाप्त किया जा रहा है। जिसमें नियमित सफाई व्यवस्था के बावजूद कुछ स्थानों पर बार-बार कचरा डाले जाने के कारण ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर विशेष सफाई कराई जा रही है तथा भविष्य में यहां दोबारा कचरा न जमा हो।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2028 से पहले मावई, मोहना और गुरावल में टॉय क्लस्टर की संभावनाओं का लिया जायजा

ग्वालियर में निवेश और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद, टॉय हब के लिए 50 कंपनियों ने दिखाई रुचि

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।



ग्वालियर. बच्चों के हाथों में पहुंचने वाले खिलौने अब ग्वालियर की औद्योगिक पहचान को भी नया आकार दे सकते हैं। खिलौना निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ी 50 उद्योगों का प्रतिनिधि मंडल शहर पहुंचा। मकसद साफ है-ग्वालियर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में टॉय क्लस्टर की संभावनाएं परखना और यहां खिलौना निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुकूल जमीन तलाशना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2028 के तहत हुई इस पहल से क्षेत्र में नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों की उम्मीद जगी है। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद निवेशकों ने मुरैना जिले के मावई, ग्वालियर के मोहना और शिवपुरी जिले के गुरावल औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया। यहां उपलब्ध औद्योगिक भूमि, आधारभूत सुविधाओं और निवेश की संभावनाओं को करीब से देखा। निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल जमीन की उपलब्धता, उसकी दरें, विकास शुल्क और सरकारी प्रोत्साहन रहे। इन मुद्दों पर अधिकारियों ने जानकारी साझा की, ताकि कंपनियां संभावित निवेश को लेकर व्यावहारिक आकलन कर सकें। निजी होटल में आयोजित बैठक में एमपीआईडीसी की कार्यकारी संचालक अनिशा श्रीवास्तव ने प्रस्तुतीकरण के जरिए मावई, मोहना और गुरावल के औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ग्वालियर जिले के बिलौआ स्थित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी। प्रतिनिधियों को उपलब्ध भूमि, दरों, विकास शुल्क और मध्यप्रदेश शासन की औद्योगिक नीतियों से अवगत कराया गया। खिलौना उद्योग के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और सब्सिडी पर भी चर्चा हुई। श्रीवास्तव ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि ग्वालियर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को एमपीआइडीसी की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विपिन निझावन, महासचिव शरद कपूर और गवर्निंग बॉडी सदस्य आशीष अग्रवाल सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। डैश फनराइड, अंकित टॉयज एंड गेम्स, लिटिल जीनियस, केस्पा टॉयज एंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नटखट और डिम्पी स्टफ जैसी कंपनियों ने भी भाग लिया। ग्वालियर में टॉय क्लस्टर विकसित होने की स्थिति में खिलौना निर्माण से जुड़ी इकाइयों को एक औद्योगिक ढांचे में विकसित करने का अवसर मिल सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, सहायक उद्योगों और निवेश गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। हालांकि, क्लस्टर की स्थापना अभी संभावनाओं के आकलन के चरण में है। भ्रमण के अंत में निवेशकों की शंकाओं के समाधान के लिए बैठक हुई, जिसमें भूमि आवंटन और सब्सिडी से जुड़े सवालों पर चर्चा की गई। अब नजर इस बात पर रहेगी कि औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण और नीतिगत जानकारी कितनी कंपनियों को ग्वालियर में निवेश के लिए आगे बढ़ाती है।

शीतला माता मंदिर हादसा मजिस्ट्रियल जांच शुरू एडीएम ने घटनास्थल का किया मुआयना

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



शीतला माता मंदिर हादसे के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के तहत एडीएम सीबी प्रसाद ने शुक्रवार को मौका मुआयना किया। जहां हादसा हुआ वह स्पॉट बारीकी से देखा और जिस ओर से ट्रक ढ़लान पर आया था उस मार्ग पर भी जायजा लिया। इसके अलावा मंदिर और आसपास की व्यवस्थाओं को लेकर भी पड़ताल की। वहीं पुलिस रिकार्ड का इंतजार है जो अभी प्रशासन को नहीं मिला है। यह रिकार्ड जांच में महत्वपूर्ण प्रशासन के अनुसार यह रिकार्ड जांच में महत्वपूर्ण है। 26 अक्टूबर से तीन दिन तक लोगों से साक्ष्य व जानकारी मांगी गई है जिसमें प्रशासन संबंधित एजेंसियों के लोगों को भी जानकारी देने के लिए बुला सकता है। जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद कर रहे हैं जांच बता दें, कि ग्वालियर में विगत 18 अक्टूबर की रात शीतला माता मंदिर के मुख्य द्वार पर ट्रक दुर्घटना के कारण हुई जनहानि के कारणों की जाच के लिये कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने अपर जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। जांच अधिकारी सीबी प्रसाद ने उपरोक्त घटना के संबंध में कहा है कि कोई भी स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति जिसका प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से हित निहित न हो, साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो, वह दिनांक 26, 27 व 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में कक्ष क्रमांक-201 में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी।

छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला, कोचिंग छोड़ने को हुई मजबूर

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



शहर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक और दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ नीट की तैयारी कर रही बारहवीं कक्षा की एक सत्रह वर्षीय नाबालिग छात्रा को इंस्टाग्राम पर बने दोस्त ने प्रेम जाल में फँसाकर ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने न सिर्फ छात्रा को होटल में ले जाकर डराया-धमकाया, बल्कि उसके अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पीड़िता रोज की तरह घर से अपनी कोचिंग के लिए निकली थी। रास्ते में उसकी मुलाकात आरुष मिश्रा नामक युवक से हुई, जिसके साथ उसकी पहचान करीब एक साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी। उस दिन आरोपी घुमाने के बहाने किशोरी को ग्वालियर किले पर ले गया। जब वापसी का समय हुआ और छात्रा ने उसे कोचिंग छोड़ने के लिए कहा, तो वह उसे बहला-फुसलकर टंकी तिराहे के पास स्थित एक होटल में ले गया। होटल के कमरे में ले जाकर आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की खौफनाक धमकी दी और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान शातिर आरोपी ने चुपके से उसके कुछ अश्लील वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। इस घिनौनी करतूत के बाद आरोपी ने छात्रा को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया या मिलने से इनकार किया, तो वह उसके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देगा।

ग्वालियर में कार्बाइड गन पर प्रतिबंध, ऑनलाइन ऑर्डर पर पुलिस की नजर, बनाने वाला गिरफ्तार

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



दीपावली पर कार्बाइड गन से होने वाले हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, प्रदर्शन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, पुलिस ने कार्बाइड गन बनाने वालों और इसकी खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गोला का मंदिर क्षेत्र में कार्बाइड गन बनाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके ठिकाने से तैयार बंदूक और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। दीपावली पर कार्बाइड गन से धमाके कर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। पुलिस बाजारों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने वाली खरीदारी पर भी नजर रखेगी। कार्बाइड गन का ऑनलाइन ऑर्डर और उसकी डिलीवरी करने वालों की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, फेब्रिकेशन शॉप, हार्डवेयर दुकानों और केमिकल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों व गोदामों की औचक जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन का प्रचार करने वालों और ई-कॉमर्स कंपनियों के स्थानीय गोदामों पर भी निगरानी रखी जाएगी।

40 मकानों पर एक्शन के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा प्रशासन, महिलाओं ने दी मशीन के आगे लेटने की धमकी

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



काला सैयद बेलदार पुरा में सरकारी जमीन पर बने 40 से अधिक मकानों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम दलबल और मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और मामले से जुड़े सभी परिवार सड़कों पर अपने-अपने घरों के दस्तावेज लेकर उतर आए। मौके पर महिलाओं ने बैकहो लोडर मशीन के आगे लेटने की धमकी भी दी। यहां पता चला कि कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके बाद रजिस्ट्रियों की जांच कर व रिकॉर्ड लेकर अधिकारी लौट आए। यहां जांच में खुलासा हुआ कि 1076 वर्गफीट जमीन थी जिसे कई बार बेचा गया और 20 हजार वर्गफीट से ज्यादा पर कब्जे दिए गए। मौके पर कार्रवाई के लिए एसडीएम नरेंद्रबाबू यादव, तहसीलदार मनीष जैन सहित अधिकारीगण पहुंचे थे। दरअसल यह पूरा मामला ग्वालियर गिर्द तहसील के ग्राम कोटा लश्कर का है। जिसमें मौजूद सर्वे क्रमांक 1887 और 1889 शासकीय भूमि पर बने 40 से अधिक मकानों से जुड़ा है, जिन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जानी थी। प्रशासन ने इन सर्वे क्रमांक पर बने मकानों को हटाने के लिए हालांकि बीते चार महीने पहले नोटिस भी जारी किए थे, इसलिए राजस्व भू अभिलेख में जमीन शासकीय दर्ज होने के कारण कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। जिसके बाद इस पौने दो बीघा जमीन पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा परत दर परत हुआ। जांच में सामने आया कि ग्राम कोटा लश्कर के सर्वे क्रमांक 1887 और 1889 की भूमि को मध्य प्रदेश भू सीमा अधिनियम 1960 के तहत सीलिंग के माध्यम से 1992 में शासकीय किया गया था। जबकि शासकीय सर्वे क्रमांक 1887 और 1889 में आरोपी कॉलोनाइजर के द्वारा निजी भूमि बता कर बेचा गया, जबकि कॉलोनाइजर की भूमि सर्वे क्रमांक 1890/1 में मात्र 1076 वर्गफुट मौजूद थी।

सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां, कमरे में बंद मिलीं बच्चियां

मदरसे से मुक्त कराए गए 22 बच्चे, बाल कल्याण समिति को मिली गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे पर प्रशासन और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 मासूम बच्चों को मुक्त कराया है। एजी ऑफिस के पास स्थित 'दारूल कुरआन मदरसे' में अवैध रूप से बच्चों को रखे जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। बाल कल्याण समिति को सूचना मिली थी कि इस मदरसे में बिना किसी मान्यता और नियमों के बच्चों को रखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा खुद विभागीय अधिकारियों और पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचीं और छापेमारी की दोपहर से शाम तक चली इस विस्तृत जांच के दौरान अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां 4 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा और देखरेख के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। बेहद चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच के दौरान अधिकारियों को तीन बच्चियां एक कमरे में बंद हालत में मिलीं। कार्रवाई



के दौरान आयोग की टीम ने मदरसा प्रबंधन से मान्यता और बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड मांगे, लेकिन प्रबंधन कोई भी वैध अभिलेख या दस्तावेज पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा। इसके बावजूद मदरसा प्रबंधन ने बच्चों को तुरंत छोड़ने की मांग की और तर्क दिया कि दस्तावेज जुटाने में समय लगता है।

शिशु गृह और शेल्टर होम में शिफ्ट किए गए बच्चे

मान्यता न होने और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बाल कल्याण समिति की निगरानी में सभी 22 बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। छोटे बच्चों को शिशु गृह और बड़े बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अन्य सुरक्षित शेल्टर होम में शिफ्ट कराया गया है। हाल ही में लापता हुआ था 13 साल का छात्र बता दें कि इसी मदरसे में रहने वाला मेवाती मोहल्ले का एक 13 वर्षीय बालक बीते 15 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इस मामले की शिकायत थाने में भी दर्ज कराई गई थी, हालांकि बाद में बालक मिल गया था। इस घटना के बाद से ही मदरसा प्रशासन की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे थे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है।

संपादकीय

भारत-अमरीका तेल गठबंधन

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप अचानक इतने विनम्र और दोस्ताना क्यों हो गए हैं? भारत के लिए अच्छी-अच्छी बातें करने लगे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत के साथ व्यापार-समझौता जरूर होगा। ट्रंप लगातार बयान देते रहे हैं कि यह समझौता अंतिम चरण में है। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो को भारत भेजा। तीन दिन के प्रवास के दौरान रूबियो ने भारत को रिफाइनिंग सुपरपॉवर करार दिया। उन्होंने रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी के अलावा अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन सरीखे शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकातें कीं। यह कमर्शियल कूटनीति का स्पष्ट संकेत है। अमरीकी विदेश मंत्री को रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी तक जाना पड़ा, क्योंकि वह जानते हैं कि वेनेजुएला के सल्फर-बहुल, भारी, निम्न दर्जे के कच्चे तेल का शोधन जामनगर रिफाइनरी ही कर सकती है। रिफाइनिंग के क्षेत्र में भारत अमरीका, चीन, रूस के बाद चौथा सक्षम देश है और जामनगर समेत भारत की 23 रिफाइनरियां दुनिया में 21 फीसदी से अधिक भागीदारी निभा रही हैं। अमरीका और यूरोप भारत के पेट्रो उत्पादों-डीजल, पेट्रोल, विमान ईंधन आदि-के बड़े खरीददार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रभुत्व का यह नया चेहरा तब सामने आया है, जब अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा जाहिर की है कि तेल के क्षेत्र में भारत-अमरीका गठबंधन बनाया जाए। भारत अमरीका का रणनीतिक साझेदार तो है, लेकिन भारत अपनी तेल-जरूरतों की पूर्ति अमरीका के जरिए कर सकता है। इस तरह अमरीका भारत के साथ संबंधों को नया आधार, आयाम और नई मजबूती देने का पक्षधर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100 फीसदी टैरिफ थोपने वाला कानून फिलहाल ठंडे बस्ते में रख दिया है, क्योंकि खुद अमरीका रूस से डीजल का आयात कर रहा है। नए परिदृश्य में हमने अमरीका से जनवरी-सितंबर में करीब 1.28 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदा था, लेकिन अक्तूबर में यह आयात घटा कर करीब 91,000 बैरल करना पड़ा। अमरीकी तेल कई दिनों बाद सप्लाई होता है और परिवहन की लागत के कारण महंगा भी पड़ रहा था।

भारत अमरीका से 8 अरब डॉलर से अधिक का तेल आयात करता है। बहरहाल भारत ने रूस से तेल का आयात जारी रखा है, लेकिन खाड़ी देशों पर निर्भरता काफी कम कर दी है। ईरान युद्ध और समुद्री मार्ग की नाकेबंदी बुनियादी वजह हो सकती है। चूंकि वेनेजुएला दुनिया में सबसे बड़ा तेल-उत्पादक और निर्यातक देश है, उस पर अब अमरीका का कब्जा है, लिहाजा विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विकल्प रखे हैं कि भारत अब रूस के बजाय अधिकतम तेल अमरीका से ही आयात करे। अमरीका ने अब प्रतिबंधों की भाषा बोलनी बंद कर दी है। अमरीका वेनेजुएला का भारी तेल रिलायंस रिफाइनरी से ही शोधित कराना चाहता है, डाटा क्षेत्र में भी अंबानी, अदाणी समूहों की काफी सक्रिय भूमिका है, लिहाजा आज अमरीका अप्रत्याशित रूप से विनम्र दिख रहा है और भारत के साथ तेल गठबंधन की बात कर रहा है। कभी अमरीका भारत को बाजार और उद्योग की चींटी मानता था, लिहाजा बात करना भी अपना अपमान समझता था, लेकिन अब विश्व और व्यापार के समीकरण बदल चुके हैं। भारत अब विश्व-व्यवस्था में महाशक्ति के तौर पर मौजूद है। यह नए दौर, नई व्यवस्था, नई सुपरपॉवर के साथ नए किस्म के राजनयिक संबंधों की शुरूआत है। वैसे भी राष्ट्रपति ट्रंप अभी अपनी राजनीति और लोकप्रियता के निम्नतम पायदान पर हैं, उन्हें करीब 31 फीसदी लोग ही समर्थन दे रहे हैं, करीब 68 फीसदी अमरीकी उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं, उनमें 37 फीसदी रिपब्लिकन समर्थक भी हैं, लिहाजा उन्हें कुछ कर दिखाने की जरूरत है। अमरीका को पेट्रो उत्पादों की सख्त जरूरत है, डीजल-पेट्रोल के दाम अप्रत्याशित स्तर पर बताए जा रहे हैं, ईरान युद्ध में अमरीका के करीब 265 अरब डॉलर फूंक दिए जा चुके हैं, लिहाजा ट्रंप रक्षात्मक स्थिति में हैं कि लोकप्रियता को कैसे बहाल किया जाए? भारत इस संदर्भ में मदद कर सकता है।

जिम्मेदारी के कानून से रुकेंगे भगदड़ के हादसे

> देश में हादसों की पुनरावृत्ति से यही लगता है कि देश के नेताओं और अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं की निगाहें वोट बैंक और अफसरों की सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती हैं। यही वजह है कि हादसे दर हादसे होते रहते हैं और देश की नौकरशाही पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। इसका कारण है कि अभी तक देश में ऐसे हादसों की जिम्मेदारी का कोई कानून नहीं बना है।

भीड़ की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम और स्मार्ट कंट्रोल रूम का उपयोग किया जाना चाहिए। भगदड़ अक्सर झूठी अफवाहों या अचानक घबराहट से होती है। इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए लगातार सही और स्पष्ट सूचनाएं दी जानी चाहिए। हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने भीड़ नियंत्रण और सामूहिक समारोहों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक और निवारक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों से भीड़ संभालने के लिए प्रशिक्षित करना है। लेकिन इन दिशा निदेर्शों की देशभर में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

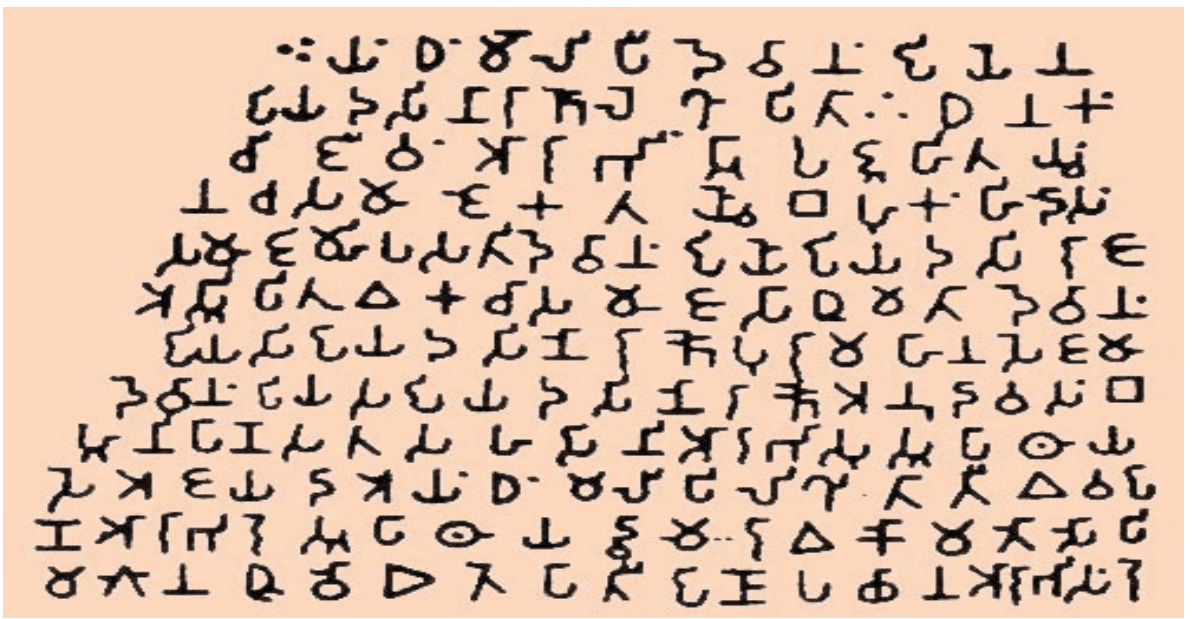
देश में हादसों की पुनरावृत्ति से यही लगता है कि देश के नेताओं और अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं की निगाहें वोट बैंक और अफसरों की सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती हैं। यही वजह है कि हादसे दर हादसे होते रहते हैं और देश की नौकरशाही पर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। इसका कारण है कि अभी तक देश में ऐसे हादसों की जिम्मेदारी का कोई कानून नहीं बना है। उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की शाम तेज बारिश के बीच पंडाल के गिरने की एक चेतावनी के बाद मची भगदड़ में 19 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। अब इस हादसे के बाद जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। इसकी न्यायिक जांच की घोषणा की गई है। दरअसल इस देश में नौकरशाह सबसे सुरक्षित हैं। देश में आज तक जितने भी बड़े हादसे हुए हैं, इनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से हुए हैं। लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। भारत में धार्मिक आयोजनों, मंदिरों, मेलों और रेलवे स्टेशनों पर समय-समय पर कई बड़ी भगदड़ की घटनाएं आजादी के बाद से होने लग गई थी। आजादी के बाद पहली बार कुंभ मेले में 3 फरवरी 1954 को, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में स्नान करने के दौरान भगदड़ मचने से 800 लोग नदी में डूबकर मर गए थे। इसी तरह 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेले में 200 लोगों की जान चली गई। यह अराजकता तब फैली जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे। जब सुरक्षाकर्मियों ने आम लोगों को नदी के किनारे जाने से रोक दिया, तो बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। साल 2003 में महाराष्ट्र के नासिक कुंभ मेले में भगदड़ मचने से 39 लोग मारे गए थे। फरवरी 2013 में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने की त्रासदी में 42 लोगों की जान चली गई थी। इन हादसों से नेताओं और अफसरों ने कोई सबक नहीं सीखा। फलस्वरूप हादसों की पुनरावृत्ति देश में होती रही। प्रयागराज में हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं, 90 लोग घायल हो गए। इंदौर में एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह जनवरी 2022 में जम्मू-कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2015 में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। साल 2014 में पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई। हादसों की इस श्रृंखला में 19 नवंबर 2012 पटना में छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हरकी पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। हादसे लगातार पूरे देश में होते रहे हैं, राज्यों की सरकारों ने दूसरे प्रदेशों में हुए हादसों से कुछ नहीं सीखा। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। वर्ष 2008 में राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए।

साल 2008 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई, 47 घायल हो गए। महाराष्ट्र में मंधारदेवी मंदिर में 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई थी। भारत में भगदड़ जैसे हादसों को रोकने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा मौजूद है। मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को इस दिशा में नीतियां और दिशानिर्देश बनाने की वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है। एनडीएमए ने विशेष रूप से बड़े आयोजनों, त्योहारों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ को संभालने के लिए ह्यमैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स एंड वेन्यूज ऑफ मास गैदरिंगह्न नाम से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उस जगह की अधिकतम क्षमता का आकलन करना अनिवार्य है, ताकि क्षमता से अधिक लोग वहां न जुटें। आयोजन स्थलों पर आने और जाने के रास्ते बिल्कुल अलग और स्पष्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपातकालीन निकास की भी उचित व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए।

भीड़ की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम और स्मार्ट कंट्रोल रूम का उपयोग किया जाना चाहिए। भगदड़ अक्सर झूठी अफवाहों या अचानक घबराहट से होती है। इसके लिए लाउडस्पीकर के जरिए लगातार सही और स्पष्ट सूचनाएं दी जानी चाहिए।

लिपियों को बचाने की जरूरत

भारत में अब तक अरबी लिपि को फारसी लिपि कहने का प्रचलन भी हो गया था। इस अरबी फारसी लिपि ने शारदा लिपि को खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर में शारदा पर मार तो पड़ी, साथ ही मजहब पर भी मार पड़ी। कश्मीरियों को बल छल से इस्लाम मजहब या शिया मजहब में शामिल किया गया। शिया मजहब या इस्लाम मजहब में गए कश्मीरियों ने शायद सोचा होगा कि अपना मूल मजहब छोड़ने के साथ अपनी शारदा लिपि को छोड़ना भी जरूरी है। कश्मीरियों ने अपनी लिपि शारदा से धोखा किया। इस प्रकार वे अपनी विरासत और अपने पूर्वजों से दूर होते गए। कश्मीरी भाषा के शारदा लिपि में लिखे हजारों ग्रन्थ कश्मीरियों के लिए अनजाने हो गए हैं।



कुलदीप चंद अग्निहोत्री

अब कश्मीर में कश्मीरी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। शिक्षा संस्थानों में अरबी लिपि में ही पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी भी इक्का दुक्का बुजुर्ग लोग कहीं कहीं शारदा लिपि के जानकार मिल जाते हैं। लेकिन शारदा लिपि को पढ़ सकने वालों की संख्या अब मुश्किल से उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। कश्मीरियों की जो पीढ़ी आतंकवाद के दिनों में कश्मीर से बाहर चली गई थी, उनके बच्चों का तो लिपि की बात तो दूर, कश्मीरी भाषा से भी नाता टूटता जा रहा है। शारदा लिपि की स्थिति भी ब्राह्मी लिपि जैसी बनती जा रही है। इससे ज्ञान की एक पूरी परम्परा और इतिहास लुप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो हट चुका है। अब जरूरत है कि शारदा लिपि में भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय शायद देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो शारदा लिपि में कश्मीरी भाषा का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है। सप्त सिन्धु फाऊंडेशन ने अभी हाल में शारदा लिपि में शारदा लोक नाम की कश्मीरी भाषा की पत्रिका शुरू की है।

भाषा और लिपि के अंतर को समझना जरूरी है। हर व्यक्ति कोई न कोई भाषा तो बोलता ही है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह जो भाषा बोल रहा है उसे लिख व पढ़ भी सके। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हिन्दी या पहाड़ी, या मंडियाली या किन्नौरी बोल रहा हो लेकिन यदि आप उसे कहें कि आप जो बोल रहे हो उसे लिख कर दिखाओ तो हो सकता है इसमें असमर्थ हो। जब लिख नहीं सकता तब लिखे हुए को पढ़ना तो सम्भव ही नहीं है। यदि भाषा को लिखना हो और बाद में उसे पढ़ना हो तो उसके लिए अक्षरों की जरूरत पड़ती है। इन अक्षरों को ही लिपि कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर में अक्षर तो भिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं ए, बी, सी आदि लिखा जा रहा है, कहीं अलफ, बे, पे और कहीं क, ख, ग लिखा जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि दुनिया भर में अनेक लिपियां प्रचलित हैं और उनके नाम भी अलग अलग हैं। पंजाबी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं जिस लिपि में लिखी जाती हैं, उसे रोमन लिपि कहा जाता है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और बोड़ो भाषाएं जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी लिपि का प्रचलन समाप्त हो गया तो उस लिपि में लिखी हुई हजारों पुस्तकों को पढ ?ा असंभव हो जाएगा। इसके कारण ज्ञान का खजाना ही नहीं समाप्त होता, बल्कि वह भाषा बोलने वालों का अपने पूर्वजों से संबंध भी टूट जाता है।

ब्राह्मी लिपि की यही स्थिति है। आज उसको पढ ? वाला कोई नहीं बचा है। दस हजार साल पहले की सरस्वती-सिन्धु सभ्यता को समझने में आ रही मुश्किलों में से सबसे बड़ी मुश्किल यही है। शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा हुआ है। लेकिन वह क्या है, इसे कोई नहीं बता सकता क्योंकि आज ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला कोई नहीं है। पीछे तमिलनाडु सरकार ने ब्राह्मी लिपि पढ़ने के लिए दस करोड़ का ईनाम घोषित किया है। लेकिन हमारा संबंध सप्त सिन्धु क्षेत्र की एक प्राचीन शारदा लिपि को लेकर है। कश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती थी। यह लिपि इतनी प्राचीन है कि कश्मीर में तो संस्कृत के अनेक ग्रन्थ भी शारदा लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। लेकिन जब मध्य एशिया से अरबों, तुर्कों और मुगलों (एटीएम) के आक्रमण शुरू हुए तो उसका पहला शिकार यह सप्त सिन्धु क्षेत्र ही हुआ। हमलावरों ने बाकी जो नुकसान किया वह तो है ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा आक्रमण यहां की लिपियों पर हुआ। उन्होंने यहां की सभी लिपियों को समाप्त कर सभी भाषाएं अरबी लिपि में लिखना शुरू कर दीं। बलोची, पश्तो, हिन्दी सब अरबी भाषा में लिखी जाने लगीं। एटीएम के एक अभियान की शिकार कश्मीर की अति प्राचीन लिपि शारदा हो गई। शासकीय प्रयत्नों के चलते वहां अरबी लिपि का प्रचार और प्रयोग हुआ। भारत में अब तक अरबी लिपि को फारसी लिपि कहने का प्रचलन भी हो गया था। इस अरबी फारसी लिपि ने शारदा लिपि को खाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कश्मीर में शारदा पर मार तो पड़ी, साथ ही मजहब पर भी मार पड़ी। कश्मीरियों को बल छल से इस्लाम मजहब या शिया मजहब में शामिल किया गया। शिया मजहब या इस्लाम मजहब में गए कश्मीरियों ने शायद सोचा होगा कि अपना मूल मजहब छोड़ने के साथ अपनी शारदा लिपि को छोड़ना भी जरूरी है। कश्मीरियों ने अपनी लिपि शारदा से धोखा किया। इस प्रकार वे अपनी विरासत और अपने पूर्वजों से दूर होते गए। कश्मीरी भाषा के शारदा लिपि में लिखे हजारों ग्रन्थ कश्मीरियों के लिए अनजाने हो गए हैं। वे उन्हें पढ़ नहीं सकते। शारदा लिपि को पुनः प्रयोग में लाने की बात एक बार फिर उठी थी जब अंग्रेजों के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अलग संविधान सभा का गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर का नया संविधान बन रहा था। उसमें कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा का प्रश्न आया। भाषा विज्ञान के कुछ जानकार सदस्यों ने कहा कि कश्मीरी भाषा की लिपि तो शारदा ही है। उसे ही संविधान में दर्ज किया जाना चाहिए। उस वक्त जम्मू कश्मीर पर अरबों, तुर्कों या मुगलों का राज नहीं था। संविधान सभा में खांटी कश्मीरी नेशनल कान्फ्रेंस का बहुमत था। उस बहुमत ने कहा कि कश्मीरी भाषा की लिपि अरबी होगी, शारदा नहीं। किसी ने ठीक ही कहा था- इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे।। अब कश्मीर में कश्मीरी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। शिक्षा संस्थानों में अरबी लिपि में ही पढ़ाई जाती है। लेकिन अभी भी इक्का दुक्का बुजुर्ग लोग कहीं कहीं शारदा लिपि के जानकार मिल जाते हैं। लेकिन शारदा लिपि को पढ़ सकने वालों की संख्या अब मुश्किल से उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। कश्मीरियों की जो पीढ़ी आतंकवाद के दिनों में कश्मीर से बाहर चली गई थी, उनके बच्चों का तो लिपि की बात तो दूर, कश्मीरी भाषा से भी नाता टूटता जा रहा है।

शारदा लिपि की स्थिति भी ब्राह्मी लिपि जैसी बनती जा रही है। इससे ज्ञान की एक पूरी परम्परा और इतिहास लुप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो हट चुका है। अब जरूरत है कि शारदा लिपि में भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय शायद देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो शारदा लिपि में कश्मीरी भाषा का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है। सप्त सिन्धु फाऊंडेशन ने अभी हाल में शारदा लिपि में शारदा लोक नाम की कश्मीरी भाषा की पत्रिका शुरू की है जिसकी लिपि शारदा है। जम्मू में संजीविनी शारदा केन्द्र भी शारदा लिपि को सिखाने का उपक्रम करता रहता है। लेकिन ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। जम्मू कश्मीर सरकार को शुरू में कम से कम यह व्यवस्था तो जरूर करनी चाहिए कि अरबी लिपि के अलावा शारदा लिपि में भी लिखने की आधिकारिक अनुमति दे। लिपियों के नष्ट हो जाने से हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। अपनी परंपराओं और संस्कृति से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए लिपियों को जिंदा करने के लिए ठोस उपाय करने की सख्त जरूरत है।

खरीफ वर्ष 2026 की समीक्षा और रबी 2026- 27 की तैयारी की बैठक, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की हुई समीक्षा

किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलें खाद बीज एवं अन्य कृषि अनुदानः गुप्ता

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के सी गुप्ता ने कहा है कि रबी 2026- 27 के लिए प्रदेश के किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद, बीज एवं अन्य कृषि अनुदान सुगमता से प्राप्त हों. इसके लिए कृषि, सहकारिता और अन्य सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें. प्रदेश में खाद बीज आदि की पर्याप्त उपलब्धता है. किसानों को फसलों के विविधीकरण, उर्वरक के संतुलित उपयोग, प्रमाणित बीजों के प्रयोग, नराली न जलाने और आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए. इस वर्ष किसानों को फसलों की जल्दी बुवाई के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे वे वर्तमान में मिट्टी में उपलब्ध नमी का उपयोग कर सके। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता की अध्यक्षता में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के लिए खरीफ वर्ष 2026 की समीक्षा और रबी 2026- 27 की तैयारियों सम्बन्धी बैठक शनिवार को अपेक्स बैंक के सभागार में संपन्न हुई. बैठक में आयुक्त भोपाल संभाग श्री कर्मवीर शर्मा, आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, आयुक्त सहकारिता, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, प्रबंध संचालक सहकारी विपणन संघ, सचिव पशुपालन एवं डेयरी, प्रबंध संचालक मत्स्य पालन, दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थिति थे.बैठक के प्रारम्भ में संभागायुक्त भोपाल श्री कर्मवीर शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि इस बार शासन द्वारा किसानों को खाद्य वितरण



व्यवस्था को अत्यंत सुगम बनाया गया है। किसान घर बैठे ही खाद के लिए व्हाट्सएप से टोकन जनरेट कर सकते हैं, पंचायत स्तर पर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। फसल बोने वाले प्रत्येक किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाएगा। श्री गुप्ता ने अधिकारियों को खाद्य वितरण पर विशेष ध्यान देने और इसकी माइक्रो प्लानिंग के निर्देश दिए. इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि किसान को खाद्य प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिए की नकली और अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक के विक्रय को सख्ती से रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, न केवल उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, अपितु उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उप संचालक कृषि ऐसे प्रकरणों में स्वतः संज्ञान लेकर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करें। श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि नरवाई जलाने को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए किसानों को समझाइश दी जाए तथा हार्वेस्टर के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए। हर हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगा होना चाहिए, इससे नरवाई मिट्टी में मिल जाती है. किसानों को फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाए जाने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने मंडियों को आधुनिक और किसानों के लिए सर्वसुविधा युक्त बनाए जाने पर भी जोर दिया।किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव श्री निशांत बरबड़े ने बताया कि इस वर्ष अलनीनो की आशंका के मद्देनजर किसानों को फसलों की जल्दी बुवाई और कम पानी वाली फसलों गेहूं, अलसी, सरसों, मसूर, मटर आदि को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. साथ ही किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों और कृषि यंत्रों के प्रयोग के लिए भी कहा जा रहा है, जिन जिलों में प्रेशराइज्ड सिंचाई प्रणाली है वहां किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर लगाए जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मंत्री पटेल में भोपाल हाट में 21वें रीजनल सरस मेले का किया शुभारंभ

महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को मिला सशक्त बाजारः 15 राज्यों के शिल्पी ले रहे भाग

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरस मेला महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का एक प्रभावी और महत्वपूर्ण मंच है। यह आयोजन ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उनके उत्पादों को एक नई पहचान दिलाने, नए बाजार से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सशक्त पहल है। मंत्री श्री पटेल ने भोपाल हाट परिसर में 21वें रीजनल सरस मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह भी उपस्थित रहीं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भोपाल हाट में यह लगातार 21वां सफल आयोजन है, जो महिला



सशक्तिकरण को नई गति दे रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा

सरस मेला 4 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा

प्रायोजित और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक संचालित रहेगा। इस मेले में देश के 15 राज्यों के 52 स्व-सहायता समूहों, मध्य प्रदेश के 45 जिलों के लगभग 104 महिला समूहों तथा विकास आयुक्त से जुड़े 45 शिल्पियों सहित कुल 201 स्वरोजगारियों ने पंजीयन कराया है। मेले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं चंदेरी साड़ियां, धार का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट, बनारसी सिल्क, चमड़े के उत्पाद, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़ी उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रदर्शन और विक्रय कर रही हैं। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय निगम ने बताया कि खरीदारी के साथ-साथ मेले में आगंतुकों के स्वाद और मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। फ़ूड ज़ोन में सिक्किम के मिलेट मोमोज, सोया व दम आलू, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध चाट व लिट्टी-चोखा, बालाघाट के लहसुन एवं मिलेट के चीले तथा उज्जैन की प्रसिद्ध चाट के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी और बच्चों के खेल-कूद के साधन भी उपलब्ध हैं। यह मेला प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा।

प्रदेश के 208 वृंदावन ग्रामों में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता होगी

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, उन्नत देशी नस्ल की गायों के पालन को प्रोत्साहित करने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। पहले साल चयनित 208 वृंदावन ग्रामों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के माध्यम से उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादक गायों की पहचान कर पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता 27 से 31 अक्टूबर तक रहेगी। प्रतियोगिता में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालक को 1 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालक को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है। प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रतियोगिता के माध्यम से पशुपालकों को बेहतर नस्ल की गायों के पालन, दूध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस पहल से प्रदेश में देशी गोवंश के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत गिर, साहीवाल, थारपारकर, मालवी, निवाड़ी सहित अन्य उन्नत अधिसूचित स्वदेशी नस्लों के संवर्धन पर विशेष जोर दिया जाएगा। योजना के द्वितीय वर्ष 2027-28 से वर्ष 2030-31 तक प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में विकासखंड स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ अभियान के तहत निकाली रैली, खुले मंच पर छात्र नेताओं ने रखे विचार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) भोपाल महानगर ने शनिवार को टीटी नगर स्थित अटल पथ पर 'अराजकता रोको, लोकतंत्र अपनाओ' आह्वान के तहत विद्यार्थी हुंकार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी और मध्यभारत प्रांत के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इसके बाद खुले मंच पर छात्र नेताओं ने लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विचार रखे। अभाविप ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन मताधिकार के माध्यम से होता है और चुनाव या संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का समाधान कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए। डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने संबोधन में मध्यप्रदेश के विकास और राष्ट्रवादी विचारधारा की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह और नेहा बोरा को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणियां कीं। वहीं, प्रांत



मंत्री केतन चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और नेहा बोरा की भी आलोचना की तथा कहा कि युवा संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था बनाए रखेंगे। अभाविप ने कहा कि वैचारिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए। संगठन ने विद्यार्थियों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखने, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने और राष्ट्रहित के प्रति सजग रहने का आह्वान किया।

भोपाल मंडल ने प्रथम छमाही में 741 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड किए जारी

दिव्यांग यात्रियों की बेहतर सेवा हेतु भोपाल रेल मंडल संकल्पित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने के लिए भोपाल रेल मंडल लगातार प्रयासरत है। मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया के नेतृत्व में, गत वितीय वर्ष में कुल 1413 रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड जारी किए गए। वर्तमान वितीय वर्ष के प्रथम छमाही सितम्बर माह तक कुल 741 रियायत कार्ड जारी किए गए है। इन रियायत कार्डों के माध्यम से दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट के साथ-साथ नियमानुसार परिचारक के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। भोपाल रेल मंडल का यह कदम सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों का लाभ अधिक से अधिक योग्य यात्रियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए दिव्यांग यात्रियों को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और रियायत प्रमाणपत्र (व्यक्ति जो बिना सहचर के यात्रा नहीं कर सकता, डॉक्टर द्वारा



प्रमाणित किया गया हो) को वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी सूचना प्रार्थी को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। आवेदक को फॉर्म भरते समय सावधानीपूर्वक सही जानकारी देनी चाहिए। जारी किए गए रियायत कार्ड की जानकारी रेलवे के सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी जाती है, जिससे टिकट बुकिंग के समय केवल रियायत कार्ड की फोटो कॉपी दिखाकर किराए में छूट का लाभ लिया जा सकता है। यह सुविधा ई-टिकट पर भी उपलब्ध है। भोपाल मंडल में रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने हेतु किसी भी कार्यदिवस में दिव्यांग सेल से अधिक जानकारी के लिए या हेल्पलाइन नंबर 9630951262 पर संपर्क कर सकते हैं। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि उनकी यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे लगातार कार्यरत रहेगा। दिव्यांग यात्रियों के हित में इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

4 नवंबर तक चलेगा मेला, महिला स्व-सहायता समूहों और शिल्पियों के 201 स्वरोजगारियों की भागीदारी

भोपाल हाट में 21वें रीजनल सरस मेले का शुभारंभ, 15 राज्यों के उत्पाद बने आकर्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और स्थानीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भोपाल हाट परिसर में रीजनल सरस मेला-2026 का शुभारंभ शनिवार को हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रायोजन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयोजन में लगने वाला यह मेला 4 नवंबर तक चलेगा। मेले का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और राज्य मंत्री राधा सिंह की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेले में देश के विभिन्न राज्यों के साथ मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए महिला स्व-सहायता समूह अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए हैं। यहां हस्तशिल्प, हथकरघा, पारंपरिक वस्त्रों और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार की गई सामग्री की बिक्री एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। चंदेरी साड़ी, बाघ प्रिंट, बनारसी सिल्क साड़ी, चमड़े से बनी वस्तुएं और विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पाद मेले के प्रमुख आकर्षण हैं। यह आयोजन ग्रामीण महिलाओं, शिल्पियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस वर्ष मेले में 15 राज्यों के 52 स्व-सहायता समूहों ने भागीदारी के लिए पंजीकरण कराया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश के 45 जिलों से लगभग 104 स्व-सहायता समूह अपने उत्पादों के विक्रय



एवं प्रदर्शन के लिए पंजीकृत हुए हैं। विकास आयुक्त हथकरघा के अंतर्गत लगभग 45 शिल्पी भी अपने उत्पादों के साथ मेले में शामिल हैं। इस प्रकार कुल लगभग 201 स्वरोजगारियों की भागीदारी पंजीकृत की गई है। मेले में अलग-अलग क्षेत्रों की पारंपरिक कला, स्थानीय कारीगरी और वस्त्र निर्माण की विविधता देखने को मिल रही है। विभिन्न राज्यों के उत्पादों के माध्यम से आगंतुकों को देश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हथकरघा परंपरा से परिचित होने का अवसर मिलेगा। वहीं, महिला स्व-सहायता समूहों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और उपयोगिता के आधार पर ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा रीजनल सरस मेला ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने का महत्वपूर्ण मंच है। ऐसे आयोजनों से समूहों को अपने उत्पादों के विपणन, ग्राहकों से सीधे संवाद और बाजार की मांग को समझने का अवसर मिलता है। इससे ग्रामीण महिलाओं और कारीगरों के काम को पहचान मिलने के साथ उनकी आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। उल्लेखनीय है कि भोपाल हाट परिसर में अब तक 20 रीजनल सरस मेलों का सफल आयोजन हो चुका है। इस क्रम में आयोजित किया जा रहा यह 21वां रीजनल सरस मेला है।आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है। मेले में न सिर्फ कला और दस्तकारी की वस्तुएं मिल रही हैं, बल्कि विभिन्न प्रदेशों के पारंपरिक और लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंच रहे हैं।



खुशकिस्मत हूं की टाइपकास्ट नहीं हुई

रसिका दुगल ने गहरे और हटकर किरदारों को चुनकर अपना करियर बनाया है। लेकिन वह मानती हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। जहां 'मिर्जापुर' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वही रसिका का कहना है कि 'मंटो' ने उन्हें उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। रसिका ने उन किरदारों के बारे में बात की जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी।

'मंटो' ऐसे समय में मिली जब सबसे ज्यादा जरूरत थी

बातचीत में अपने करियर के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रसिका ने कहा कि 'मिर्जापुर' बेशक सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंची। लेकिन 'मंटो' ऐसे समय में मिली जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोगों ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा और जो बहुत बड़े दर्शकों तक पहुंचा, वह निश्चित रूप से 'मिर्जापुर' था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज ने मुझे उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, वह 'मंटो' थी।

रसिका का कहना है कि वह खुशकिस्मत रहीं कि एक ही तरह के किरदारों में बंधकर नहीं रह गईं। 'मिर्जापुर' में एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं लकी थी क्योंकि 'मंटो', 'मिर्जापुर' और 'दिल्ली क्राइम' लगभग एक ही समय पर रिलीज हुए थे। 'दिल्ली क्राइम' और 'मिर्जापुर' में बिल्कुल अलग-अलग किरदार थे। इसलिए मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे उस विविधता को आजमाने और दिखाने का मौका मिला। दोनों ने अपने-अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 'दिल्ली क्राइम' एक बहुत ही शानदार शो है। रसिका ने माना कि टाइपकास्टिंग से बचना हमेशा उनकी प्राथमिकता नहीं थी।



लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर शहनाज गिल ने बताया अपना अनुभव

बॉलीवुड अभिनेत्री शहनाज गिल ने हाल ही में लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इसे लेकर मन में एक डर आता है।

जब शहनाज से पूछा गया कि क्या दूर रहने से प्यार बढ़ता है या कम हो जाता है? इस पर उन्होंने कहा, 'जब दो लोग एक-दूसरे से दूर होते हैं, तो प्यार और पार्टनर की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक डर भी मन में आता है कि सामने वाला इंसान पीठ पीछे क्या कर रहा होगा। इसलिए दूरी से शक भी बढ़ जाता है।' शहनाज ने कहा, 'मेरा मानना है कि अगर प्यार सच्चा हो और पार्टनर पास हो, तो रिश्ते में किसी दूरी की जरूरत नही होती।'

आज के दौर में प्यार

जब शहनाज से पूछा गया कि आज के डेटिंग ऐप्स के जमाने में क्या ऐसा सच्चा प्यार मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि प्यार किसी भी तरह का हो, चाहे पुराने जमाने का या आज के दौर का बस दिल में सच्चा प्यार होना चाहिए। फिल्म 'इश्कनामा' एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। यह फिल्म निम्मा और नसीमा नाम के दो प्रेमियों की असल जिंदगी की कहानी है। इसकी कहानी 1981 से 1988 के बीच भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के आस-पास की है, जो प्यार, उनके त्याग और मजबूरी में अलग होने के दर्द को दिखाती है।

किस किताब पर आधारित है 'इश्कनामा'

फिल्म 'इश्कनामा', 'हिंद पाक बॉर्डरनामा' नाम की किताब पर बनी बताई जा रही है। इस फिल्म में शहनाज गिल के साथ जय रंधावा और सौरभ सचदेवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अरविंद एस. खैरा हैं। फिल्म का म्यूजिक बी प्राक ने दिया है और गाने जानी ने लिखे हैं। यह फिल्म 24 जुलाई को भारत, कनाडा और यूके समेत दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



रियलिटी शो में आता है कलाकारों का असली चेहरा, किरदार से अलग होती है पहचान

टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह 'बिग बॉस 18' में नजर आने के बाद काफी सुर्खियों में रही हैं। अब उन्होंने रियलिटी शो और एक्टिंग की दुनिया के बीच के फर्क को लेकर अपनी राय साझा की है।

उनका मानना है कि रियलिटी शो कलाकार के असली स्वभाव को समझने का मौका देते हैं। जब कोई कलाकार रियलिटी शो में आता है तो दर्शक उसे उसके निभाए किरदारों से अलग एक इंसान के रूप में जान पाते हैं। इंटरव्यू में ईशा सिंह से जब पूछा गया कि क्या रियलिटी शो किसी अभिनेता या अभिनेत्री को ज्यादा लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं, इस पर उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि इससे किसी कलाकार की लोकप्रियता कितनी बढ़ती है, लेकिन दर्शकों को अपने पसंदीदा सितारों की निजी जिंदगी के बारे में जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। लोग बिहाइंड द सीन्स जैसी चीजें इसलिए देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वे कलाकार को और करीब से जानना चाहते हैं। जब कोई कलाकार किसी रियलिटी शो में आता है तो दर्शकों को उसके असली स्वभाव, व्यवहार और पसंद-नापसंद को समझने का मौका मिलता है।''

अभिनेत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, ''दर्शक मेरे निभाए किरदारों जैसे जुही और सैयम को जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ईशा कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है और वह किस तरह की इंसान हैं, यह जानने का मौका रियलिटी शो से ही मिलता है। रियलिटी शो में कोई किरदार नहीं होता और न ही कोई अभिनय का पर्दा होता है, बल्कि वहां कलाकार खुद के रूप में सामने आता है।''

ईशा सिंह ने कहा, ''यही वजह है कि दर्शकों का कलाकारों के साथ एक अलग जुड़ाव बन जाता है। लोग सिर्फ किसी कलाकार का काम ही नहीं देखना चाहते, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि वह अपनी निजी जिंदगी में कैसा है। दर्शकों को यह जानने में भी दिलचस्पी होती है कि कोई कलाकार क्या पहनता है, कैसे तैयार होता है, क्या खाता है और उसका व्यवहार कैसा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''रियलिटी शो और फिक्शन शो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। दोनों का अपना अलग महत्व और अलग दर्शक वर्ग होता है। रियलिटी शो में कलाकार का निजी पक्ष सामने आता है, जबकि अभिनय में कलाकार किसी कहानी और किरदार को जीता है। रियलिटी शो की अपनी अलग ऑडियंस होती है। आज कई तरह के रियलिटी शो बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक्टिंग पूरी तरह अलग चीज है। यह बिल्कुल अलग तरह का क्षेत्र है।''



'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मैं जिंदगी भर याद रखूंगी

अभिनेत्री यामी गौतम को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। उन्हें फिल्म 'आर्टिकल 370' में बेहतरीन अदाकारी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इस कामयाबी से अभिनेत्री खुश हैं। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। अभिनेत्री ने पुरस्कार मिलने के बाद एक्स पर लिखा 'हर सफर में एक ऐसा पल आता है, जो आपको याद दिलाता है कि आपने हार क्यों नहीं मानी। आज मेरे लिए वही पल है। 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे लिए एक ऐसा सम्मान है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी।' उन्होंने आगे लिखा 'चौदह वर्षों से, मैंने बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहने, ईमानदारी से काम करने और अपनी परफॉर्मेंस को ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है। यह सम्मान उम्मीद, हिम्मत, मजबूती और सिनेमा के लिए अटूट प्यार से भरे सफर का नतीजा लगता है। यह एक ऐसा सपना है, जिसे मैंने वर्षों से अपने दिल में संजोकर रखा था और आज, मैं इसे बहुत आभार और विनम्रता के साथ स्वीकार कर रही हूं।'



यामी ने जताया आभार

उन्होंने फिल्म 'आर्टिकल 370' को चुनने के लिए और इसे पुरस्कार देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने लिखा 'मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे शुभचिंतकों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के हर दौर में मुझ पर भरोसा किया। आपके भरोसे ने मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी, तब भी जब मंजिल बहुत दूर लगती थी।'



'आर्टिकल 370' को तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर गदगद हैं आदित्य धर

बीते दिनों 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं के नाम का एलान हुआ। यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा फिल्म ने दो और पुरस्कार जीते हैं। इसी फिल्म के लिए यामी गौतम के नाम का एलान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए शशवत सचदेव ने पुरस्कार जीता है। इस पर आदित्य धर ने रिएक्शन दिया है।

आदित्य धर ने जताई खुशी

बता दें कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2024 के लिए प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं का एलान हो चुका है। 'आर्टिकल 370' को तीन पुरस्कार मिलने पर आदित्य धर गदगद हैं। उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। 'धुरंधर' डायरेक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर खुशी जताई है और यह वादा किया है कि वे इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे।

शब्दों में बयां करना मुश्किल

आदित्य धर ने लिखा है, 'फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए तीन नेशनल अवॉर्ड जीतना एक ऐसा पल है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह अनुभव मुझे विनम्र और भावुक बनाता है और मेरा दिल गहरे आभार से भर देता है। जब हमने यह फिल्म बनाने का फैसला किया, तो हमारा मकसद अवॉर्ड पाना नहीं था। हम ईमानदारी, हिम्मत और सच्चाई के साथ एक कहानी कहने के पक्के इरादे से प्रेरित थे। यह देखना वाकई बहुत सुखद है कि देश भर के दर्शकों ने इस सफर को पसंद किया और अब इसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है।

ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे

आदित्य ने आगे लिखा है, 'जियो स्टूडियोज में हमारे पार्टनर्स, खासकर ज्योति देशपांडे का दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अटूट भरोसे के साथ इस फिल्म का साथ दिया और सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया। पुरस्कार मिलना खुशी तो है ही, साथ ही वे आगे की जिम्मेदारी की याद भी दिलाते हैं। यह सम्मान हमारे इस भरोसे को और मजबूत करता है कि ईमानदारी, पक्के इरादे और मकसद के साथ कही गई कहानियां हमेशा अपनी जगह बना ही लेती हैं। यह मंजिल नहीं है। यह एक वादा है कि हम नई सीमाएं तय करते रहेंगे, ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे, जो मायने रखती हैं और ऐसा सिनेमा बनाते रहेंगे जो बातचीत शुरू करे। भावनाओं को जगाए और एक गहरी छाप छोड़े। दिल की गहराइयों से... धन्यवाद। यह सम्मान हम सभी का है। जय हिंद'।

यामी और प्रियामणि के अभिनय को सराहा

इस शानदार सम्मान के लिए सम्मानित जूरी का और उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 'आर्टिकल 370' देखी, उसे सपोर्ट किया, उस पर चर्चा की और उसमें भरोसा जताया। आपके प्यार ने इस फिल्म को स्क्रीन से परे एक नई जिंदगी दी। यह सम्मान हमारे बेहतरीन डायरेक्टर, आदित्य सुहास जांभले का है, जिनकी सोच और पक्के इरादे ने हर फ्रेम को आकार दिया। यामी गौतम और प्रियामणि का भी शुक्रिया, जिन्होंने अपनी एक्टिंग में इतनी गहराई, मजबूती और सच्चाई दिखाई। शाश्वत सचदेव का भी धन्यवाद, जिनका संगीत हमारी कहानी कहने की कला की जान बन गया। हमारी कास्ट और क्रू के हर सदस्य का भी शुक्रिया, जिनकी लगातार मेहनत, जुनून और भरोसे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया'।



खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कई प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने

दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है सघन जांच

6.76 लाख का मावा जप्त, तेल की पैकिंग यूनिट पर भी छापा

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



कलेक्टर भिण्ड श्री पवन कुमार जैन के निर्देशन पर दीपावली के त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों एवं मावा को परिवहन करने वाले वाहनों की अभियान चलाकर सघन जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरण सेंगर ने गोहद चौराहे के पास जैन मंदिर वाली गली में स्थित शीतला दुर्गा डेयरी की रैपिड किट से जांच की, संदेह होने पर दूध का नमूना लिया एवं अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर धारा 32 का नोटिस दिया। गोहद चौराहे पर रमेश सिंह तोमर की कृष्णा डेयरी से मावा का नमूना भी लिया। इसी क्रम में श्रीमती किरण सेंगर ने गोहद चौराहे पर राम लखन तोमर फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया जहां टीआर ब्रांड नाम से पैक हो रहे सरसों तेल का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिया, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर राम लखन तोमर फूड प्रोडक्ट्स को धारा 32 का नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल ने तहसील मेहगांव में सुबह 11:00 बजे सतेन्द्र सिंह ग्राम सोनी के वाहन क्रमांक एमपी 07 जी 6467 का निरीक्षण किया, जिसमें मावे की 65 डलियां परिवहन हेतु रखी थीं। वाहन? के मालिक सतेन्द्र सिंह ने मावे की डलियों के मालिकों के नाम कमलेश डेयरी ग्राम रजपुरा, रामगोपाल डेयरी ग्राम मृगपुरा, संजू डेयरी ग्राम मुड़िया खेड़ा, बजरंग डेयरी ग्राम सोनी बताये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल ने मौके पर मावे के कुल चार नमूने लेकर 2600 किलोग्राम मावा जप्त किया, जिसकी कीमत लगभग 676000/- रूपये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री रेखा सोनी ने श्रीमती निधि नीलेश श्रीवास्तव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल एवं नगर पालिका की टीम के साथ शहर में स्थित होटलों का निरीक्षण किया। टीम ने डायवर्सन रोड़ जनता स्कूल के पास स्थित होटल नारायणी हाइट्स का निरीक्षण कर मौके पर मिली एक्सपायरी डेट के ब्रेड एवं पाव को नष्ट कर धारा 32 का नोटिस जारी किया। इसके बाद टीम ने किरार कॉलोनी स्थित होटल किंग्स इंपीरियल का निरीक्षण किया, जहां श्रीजी ब्रांड के छेना पाउडर के एक्सपायरी डेट के पैकेट एवं सड़ा हुआ धनिया व ब्रोकली को मौके पर ही नष्ट कराया गया। फ्रीजर में रखे पनीर एवं तेल श्री ब्रांड की सरसों तेल का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लेकर धारा 32 का नोटिस जारी किया गया।

संचालक स्कूल शिक्षा विभाग एवं उपसंचालक लोक शिक्षण ने मेहगांव गोहद के स्कूलों का किया निरीक्षण



एक सत बुलेटिन, भिण्ड

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत गत दिवस स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारियों द्वारा भिण्ड जिले के शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयीन अधोसंरचना का निरीक्षण किया गया। संचालक स्कूल शिक्षा विभाग श्री डी.एस. कुशवाह ने सांदीपनि विद्यालय मेहगांव और उपसंचालक लोक शिक्षण श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी ने सांदीपनि विद्यालय गोहद, सांदीपनि विद्यालय मेहगांव तथा पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव का निरीक्षण किया। अभियान के अंतर्गत अधिकारी जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं और लोकसेवाओं की जमीनी स्थिति परख रहे हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षाओं का संचालन, भवन एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने बच्चों से सीधे संवाद कर पढ़ाई के स्तर और विद्यालय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।

विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सिहोरा के हितों की रक्षा अब पार्टी करेगी

अरुण यादव वोट बचाओ देश बचाओ कैंपेन के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बने



एक सत बुलेटिन, सिहोरा

प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बीते 23 साल में प्रदेश की राजनीति में सबसे अग्रणी सिहोरा की घर अपेक्षा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बीते 23 साल में प्रदेश की राजनीति में सबसे अग्रणी सिहोरा की घोर उपेक्षा की है लेकिन अब समय बदल गया है अब आमजन का भाजपा से मोहभंग हो गया है प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस आने पर सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में 1 अक्टूबर 2003 में बने सिहोरा जिला में कलेक्टर एसपी बैठक सिहोरा के हितों की रक्षा की जाएगी यह बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अरुण यादव ने उनके कांग्रेस पार्टी के वोट बचाओ देश बचाओ कैंपेन राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनने पर बधाई देने पहुंचे सिहोरा विधानसभा के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से कही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अरुण यादव को ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा पूरे देश में चलाई जा रहे वोट बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय कैंपेन का नेशनल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने पर अरुण यादव के निवास पर आयोजित स्वागत में कार्यकर्ता सिहोरा विधानसभा के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए अरुण यादव की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से होने पर पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह का वातावरण बना है राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तंखा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व विधायक लखन घनघोरिया प्रदेश सचिव राजेश चौबे ने खुशी प्रकट की है राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधि पूर्व प्रदेश सचिव बाबा कुरैशी की अगुवाई में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस मंजू मिश्रा के संयोजन में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी पटेल जिला महासचिव अमोल चौरसिया डॉ आरके यादव प्रभात कुररिया अभिषेक रिंकू शर्मा मनीष खंपरिया मनीष शुक्ला डब्बू पाठक शेख साबिर राजा पटेल अर्जुन बाजपेई संतोष पटेल अन्नू पटेल रवि सोनी बसंत तंतुवाय राममिलन पांडे हिमांशु पांडे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे।

मेरी अपील मेरा दर्द सुन लो

सिहोरा। 24 अक्टूबर को दोपहर 2:00 बजे सिविक सेंटर से डॉ आंबेडकर चौक तक ओबीसी समाज के 27% आरक्षण संख्या का अनुपात में भागीदारी जाति का जनगणना में ओबीसी का कलाम जोड़ने एवं अनुसूचित जाति जनजाति समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए पैदल मार्च निकाला जाना है सभी से निवेदन है उसे संदर्भ में हम सभी लोग 24 अक्टूबर पैदल मार्च में कैसे शामिल होंगे कितने लोग लेकर आएंगे अभी तक हम सब ने किन-किन लोगों को शामिल होने के लिए फोन किया है फोन करना है इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आंदोलन के संदर्भ में हो पर हम देखते हैं इसकी कोई चिंता नहीं एक वीडियो उठाया और डाल दिया उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है हम सब अपनी-अपनी जिम्मेदारी 24 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की साथियों को लेकर आने की काम कर ले तो ताकत जब दिखेगी तो सबकी ताकत बनेगी यह काम कोई नहीं कर रहा ग्रुप में सभी ग्रुप के लोग जितने भी हैं सभी से मेरा विनम्र निवेदन है की पूरी ताकत लगा दें पैदल मार्च के लिए और समय पर पहुंचने का कष्ट करें इसको अधिक से अधिक लोगों से चर्चा करें भैया यह हमारी लड़ाई है यह सब की लड़ाई है हम सब नेता हैं हम सब नेतृत्व करता है हम सब आयोजन करते हैं पहुंचना है कार्यक्रम में यह चर्चा हम कर ले करते रहें और लगातार अगर हम यह सब करते रहे एक दिन जबलपुर में ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति एक अच्छी ताकत हम सब जागरूक समाजसेवी बना पाएंगे ।

प्रस्फुटन समितियां ग्राम विकास में निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका, प्रस्फुटन शक्ति अभियान के अंतर्गत सेक्टर स्तरीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित

एक सत बुलेटिन, मुरैना



मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड जौरा के विकासखंड समन्वयक बी.डी. शर्मा के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था हड़वासी युवा मंडल द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय हड़वासी में प्रस्फुटन शक्ति अभियान के अंतर्गत सेक्टर क्रमांक-5 हड़वासी की प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य समितियों के सदस्यों को संगठनात्मक कार्यों, अभिलेख संधारण, संवाद कौशल तथा ग्राम विकास में उनकी भूमिका के प्रति सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सत्रों में समिति सदस्यों का पंजीयन एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नवांकुर संस्था प्रस्फुटन समिति मानपुर पृथ्वी के अलकेश राठौर ने समितियों के दस्तावेजों एवं अभिलेखों के व्यवस्थित संधारण की जानकारी दी। विकासखंड समन्वयक श्री बी.डी. शर्मा ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की गतिविधियों एवं उद्देश्यों से अवगत कराते हुए जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने में समितियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मेंटर विनोद शर्मा ने प्रस्फुटन समितियों को स्वयंसेवी संस्था के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया समझाई। वहीं, हड़वासी युवा मंडल के सचिव परीक्षित शर्मा ने प्रभावी संवाद कौशल, उसकी आवश्यकता एवं व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में प्रतिभागियों से सुझाव एवं प्रतिक्रिया प्राप्त की गई तथा उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण में प्रस्फुटन समिति चेना के करतार सिंह राजपूत, कुम्हेरी के श्री सुदामा शर्मा एवं श्री संतोष शर्मा, सांटा के ऋषिकेश शर्मा, सोनू शर्मा एवं विकास शर्मा तथा उधेड़ी के श्री रामख्तयार यादव सहित विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नवांकुर सखी श्रीमती ऊषा शर्मा, श्रीमती सुषमा, श्रीमती जगनेरी, श्रीमती नैनुका कुशवाह, श्रीमती सुनता शर्मा एवं श्रीमती ममता कुशवाह सहित नवांकुर संस्था के विष्णु तोमर, जितेंद्र शर्मा, सहदेव शर्मा, रवि तिवारी, ऋषिकेश शर्मा, विवेक शर्मा, संजय शर्मा एवं श्री दीपक शर्मा की सहभागिता रही।

पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर एक किसान पर 2500 का अर्थदण्ड अधिरोपित

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



जिले में फसल अवशेष (पराली) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्टर भिण्ड श्री पवन कुमार जैन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन के क्रम में उल्लंघन के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कमलेश सिंह नरवरिया पुत्र श्री विजय सिंह नरवरिया, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम पुर जिला भिण्ड द्वारा पराली जलाने के संबंध में किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कमलेश सिंह नरवरिया के विरुद्ध नियमानुसार 2500 (दो हजार पांच सौ रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएँ। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीवों एवं पोषक तत्वों को नुकसान पहुँचता है तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। किसान पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करें और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पराली जलाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर प्रचलित नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन ने उप संचालक कृषि को सभी एईओ अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए, यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाएगी तो संबंधित एईओ और एसएडीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम को इन घटनाओं के निस्तारण हेतु पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए।

मुरैना, उज्जैन और सागर के बाद अब देवास में जहरीली शराब का कहर! आखिर कब तक लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा? : जीतू पटवारी

देवास। मुरैना, उज्जैन और सागर के बाद अब देवास में भी जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया है। आखिर कब तक जहरीली शराब से लोगों की जान पर बनती रहेगी और जिम्मेदार महकमा आंखें मूंदे बैठा रहेगा? जहरीली शराब के कारण परिवार उजड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अरुण यादव ने देवास जिले के ग्राम चंदाना पहुंचकर जहरीली शराब की घटना में अपनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात की और उनके दुख-दर्द को करीब से जाना। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री मनोज राजानी, ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनीष चौधरी, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रयास गौतम सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे। श्री जीतू पटवारी ने कहा कि देवास जिले में जहरीली शराब से अब तक 22 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार और जिला प्रशासन को मौतों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए।



वार्ड 37 के नए संयोजक और पालक का सम्मान, जनसमस्याओं के निराकरण की उम्मीद

निर्भय सिंह यदुवंशी और राकेश जायसवाल का तुलसी नगर में स्वागत

एक सत बुलेटिन, इंदौर



भाजपा संगठन में वार्ड 37 के संयोजक निर्भय सिंह यदुवंशी और वार्ड पालक राकेश जायसवाल को नई जिम्मेदारी मिलने पर तुलसी नगर में रहवासियों ने उनका सम्मान किया। इस दौरान क्षेत्र की कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए सक्रिय पहल की अपेक्षा जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि वार्ड में तुलसी नगर, साई कृपा कॉलोनी, राधिका पैलेस, महालक्ष्मी नगर और पुष्प विहार एक्सटेंशन सहित कई कॉलोनियां आती हैं। पेयजल, सड़क, सफाई और जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए पदाधिकारी रहवासियों से संवाद कर समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में पार्षद संगीता महेश जोशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राम बाबू यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष विमला मनाग्रे, महापौर प्रतिनिधि हिमांशु अग्निहोत्री, योग गुरु नामदेवजी, बसंत नायक, संजय यादव, के.के. झा, कृष्ण कुमार वर्मा, कमलेश शर्मा, रूपेश शर्मा, मनोज दीक्षित, अमोल पाटिल, महीप धींग, विश्वास द्विवेदी, गोल्डी चौहान, सुनील राठौर, आनंद गुप्ता, राजेंद्र राठौर, ज्योति ठक्कर, गीता मिश्रा और शीतल गुर्जर सहित क्षेत्र के रहवासी मौजूद रहे।

ब्लॉक अध्यक्ष बिहारी को गोसलपुर का अतिरिक्त प्रभार

सिहोरा। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजय यादव ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहोरा अध्यक्ष बिहारी पटेल को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोसलपुर का अतिरिक्त प्रभार देकर सिहोरा गोसलपुर दोनों ब्लॉकों का संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया है यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदेश संगठन मंत्री की सहमति से राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तंखा विधायक लखन घनघोरिया प्रदेश सचिव राजेश चौबे की अनुशंसा पर की गई है वरिष्ठ सुबोध पांडे प्रकाश कुररिया सुरेंद्र मिश्रा राज्यसभा सदस्य प्रतिनिधि बाबा कुरैशी नगर अध्यक्ष पवन सोनी जिला उपाध्यक्ष मंजू मिश्रा जिला महासचिव अमोल चौरसिया पार्षद आलोक पांडे गणेश दहिया रमेश पटेल शंकर वंशकार राजेश पटेल नवनीत शुक्ला राजभान शशि कला चौधरी शेख साबिर फैज आलम शाह गुलाम कुरैशी मनीष शुक्ला मनीष खंपरिया डब्बू पाठक उमाकांत चौरसिया सत्येंद्र पटेल ने खुशी प्रकट की है।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल

रेल कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी गति: मोहन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

विंध्य क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में 24 अक्टूबर 2026 का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। सतना-देवेंद्रनगर के 53 किलोमीटर तथा रीवा-चुरहट के 65 किलोमीटर रेलखंडों का लोकार्पण किया गया। साथ ही देवेंद्रनगर-चुरहट ट्रेन सेवा का शुभारंभ हुआ। इस उपलब्धि के साथ सीधी जिले का रामपुर नैकिन-चुरहट क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़ गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन का नया साधन मिलने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की। नागौद से नगरीय विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, सतना सांसद गणेश सिंह तथा नागौद विधायक नागेंद्र सिंह ने भी वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज विंध्य और बुंदेलखंड को नई रेल सेवा की सौगात मिली है, जिससे दीपावली की रौनक





और बढ़ गई है। अब तक रेल सेवा से वंचित रहे क्षेत्र विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 541 किलोमीटर लंबी ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ेगी तथा विकास के नए अवसर खोलेगी। खनिज संसाधनों से समृद्ध इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रेल विकास के नए अवसर साकार हो रहे हैं। प्रदेश में 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगतिरत है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, उद्योगों के नए अवसर विकसित होंगे तथा युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी आसान होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज विंध्य और बुंदेलखंड के लिए विकास की लाइफलाइन जुड़ने का दिन है।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा-जिले में लिखी जा रही विकास की गाथा

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि आज जिले में विकास की गाथा लिखी जा रही है और हम सभी इस गौरवशाली क्षण के साक्षी बन रहे हैं। लंबे इंतजार और निरंतर प्रयासों के बाद यह ऐतिहासिक अवसर आया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार दिसंबर 2026 तक रेल लाइन को सीधी तक तथा वर्ष 2028 तक सिंगरौली तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और शिक्षा के अवसरों का विस्तार होगा। स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति प्राप्त होगी। सांसद ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा पूर्व सांसदों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया।

रीवा सांसद मिश्रा ने कहा-दशकों पुरानी परिकल्पना हो रही साकार

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि जिस ट्रेन सेवा की परिकल्पना वर्ष 1956 में की गई थी, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गति मिली है और यह अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। उन्होंने रेल संपर्क के विस्तार को विंध्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। सतना-देवेंद्रनगर और रीवा-चुरहट रेलखंडों के विकास से विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में उपलब्ध चूना पत्थर और अन्य खनिज संसाधनों को देखते हुए रेल मार्ग सीमेंट, क्लिंकर तथा अन्य माल के परिवहन के लिए उपयोगी होगा। इससे औद्योगिक इकाइयों को परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा-साकार हुआ वर्षों पुराना सपना

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज सपनों के साकार होने का ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने जिस रेल परियोजना की नींव रखी थी, वह वर्ष 2026 में साकार हो रही है। यह रेल लाइन प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली को रीवा और सतना के सीमेंट उद्योगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए औद्योगिक क्रांति, पर्यटन क्रांति और कृषि क्रांति आवश्यक हैं, जिनकी आधारशिला मजबूत अधोसंरचना होती है। विंध्य क्षेत्र में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से विकास की नई संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। रीवा-सीधी-सिंगरौली रेल लाइन के साथ रीवा-सीधी फोरलेन और सीधी-सिंगरौली फोरलेन सड़क परियोजनाओं पर भी कार्य प्रगतिरत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा हवाई अड्डे के लोकार्पण के एक वर्ष के भीतर ही पांच स्थानों के लिए नियमित हवाई सेवाएं संचालित होने लगी हैं और अब तक 50 हजार से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं। बेहतर रेल, सड़क और हवाई संपर्क से उद्योगों की स्थापना, कृषि उत्पादों के परिवहन, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री सारंग ने खेड़ापति हनुमान मंदिर एवं लाल परेड मैदान का किया निरीक्षण

100 करोड़ की लागत से आकार ले रहा श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं: सारंग

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने परमपूज्य संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के साथ छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगलकामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों एवं छोला दशहरा मैदान का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इसके साथ ही मंत्री श्री सारंग ने संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के साथ लाल परेड मैदान पहुंचकर 26 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले अर्चन कार्यक्रम की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि परमपूज्य संत श्री रावतपुरा सरकार महाराज जी के सानिध्य में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 26 अक्टूबर को शाम 7 बजे लाल परेड मैदान में मां राजराजेश्वरी का कुमकुम अर्चन



कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। अर्चन एवं पूजन के लिए आवश्यक समस्त सामग्री भी आयोजनकर्ताओं द्वारा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि श्रद्धालुओं को केवल कार्यक्रम में शामिल होना है। आयोजन में सहभागिता के लिए प्रवेश और पूजन सामग्री की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है।

100 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर

छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। कॉरिडोर को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर के अंतर्गत भव्य कॉरिडोर, सुगम आवागमन एवं दर्शन व्यवस्था, दर्शक दीर्घा, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक अधोसंरचना, पार्किंग सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। श्री खेड़ापति हनुमान कॉरिडोर का विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार की भावना के अनुरूप किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित, सुगम और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गुणवत्तापूर्ण लेखन के आधार पर तैयार होंगी पाठ्य पुस्तकें

भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पुस्तकों के लेखन के लिए भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित पुस्तकों के लेखन के लिए, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल में दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण, मौलिक एवं प्रामाणिक पाठ्यसामग्री तैयार करने के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से शामिल करना है। कार्यशाला में आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक डॉ. अशोक कड़ेल, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी, शिक्षाविद् डॉ. चांद किरण सलूजा तथा वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, हरियाणा के पूर्व कुलपति डॉ. रमेश चंद्र भारद्वाज सहित विषय विशेषज्ञों ने सहभागिता की। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा ने कहा कि शोध विषयक सामग्री को प्रमाणित करने के बाद ही उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यशाला में भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आधारों और प्रामाणिक स्रोतों की समीक्षा के



साथ विभिन्न संकायों एवं विषयों के अनुरूप पुस्तक लेखन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा श्री दिनेश दवे ने बताया कि कार्यशाला के आगामी सत्रों में संकायवार एवं विषयवार भारतीय ज्ञान परंपरा पर विमर्श होगा। विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक सामग्री के चयन, विषयों की योजना, भाषा-शैली, प्रश्नों, गतिविधियों एवं अभ्यासों के स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। अंतिम सत्र में संकायवार समूह चर्चा के माध्यम से पुस्तक लेखन की दिशा को आगे बढ़ाया जाएगा।

भारत मंडपम में महका बालाघाट का चिन्नौर चावल, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला मंच

भोपाल। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित तीन दिवसीय 'भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026' में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के गौरव, जी.आई. टैग प्राप्त 'बालाघाट चिन्नौर' चावल ने अपनी विशेष पहचान दर्ज कराई है। 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत चयनित इस सुगंधित चावल का सम्मेलन में भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है। 23 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) भोपाल एवं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में चिन्नौर चावल के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष स्टॉल लगाया गया है। इस वैश्विक आयोजन में बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व लालबर्रा चिन्नौर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कर रही है। एफपीओ के अध्यक्ष श्री ईशुपाल चौहान एवं संचालक सदस्य श्री राधेलाल पटले ने स्टॉल पर आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चावल निर्यातकों, व्यापारियों और प्रतिनिधियों को चिन्नौर चावल की गुणवत्ता, प्राकृतिक सुगंध और इसके औषधीय व पारंपरिक महत्व से अवगत कराया।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल श्री पटेल से की सौजन्य भेंट, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा



■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की सुबह लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। भेंट के दौरान विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल श्री पटेल को बताया कि राज्य सरकार द्वारा 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किसानों की आमदनी बढ़ाने और इनके समग्र कल्याण के लिए किये जा रहे प्रयासों, बलराम कृषि महोत्सव आयोजन और किसान कल्याण वर्ष की अब तक की प्रगति से अवगत कराया।

आगामी वर्ष को मप्र सरकार युवा वर्ष के रूप में मनायेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आगामी वर्ष (2027) को मप्र सरकार युवा वर्ष के रूप में मनायेगी। युवा वर्ष 2027 में सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर उनके कौशल विकास और स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित कर युवाओं को उद्यमी से उद्योगपति बनाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें, कमियों पर जवाबदेही तय कर करें कार्रवाई : यादव

भोपाल। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा औचक निरीक्षण और निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की जा रही है। प्रबंध संचालक म.प्र. सड़क विकास निगम श्री भरत यादव ने 7 जिलों के 35 निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता संबंधी कमियों पर जवाबदेही तय करने और आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण दलों की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। विभाग के 7 निरीक्षण दलों ने 22 अक्टूबर को विदिशा, बालाघाट, श्योपुर, बड़वानी, मऊगंज, शाजापुर एवं दमोह जिलों में रैंडमली चयनित 35 निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इनमें लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल) के 21, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू-भवन) के 6, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 07 तथा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का एक कार्य शामिल था। निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। समीक्षा में बड़वानी जिले में पीजी योजना के अंतर्गत 20.89 किलोमीटर लंबे बलवाड़ी-देवली-धवली मार्ग की कार्य स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य अभियंता, इंदौर को संबंधित ठेकेदार मेसर्स सोरथिया वेलजी रत्ना एंड कंपनी, वडोदरा के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। बड़वानी-बंधान-अंबापानी-सिंधी-खोदरा-सिलावद मार्ग का कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण पाया गया।

भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ मॉड्यूल के संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन में उमड़ा अधिकारियों का उत्साह- एकता और समर्पण का दिखा स्वरूप

'आपकी बात, आपके साथ' ने दिया संगठन को नई ऊर्जा का संकल्प

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ, भोपाल सर्कल के भोपाल मॉड्यूल द्वारा आरबीओ-1, आरबीओ-2 एवं आरबीओ-9 तथा एलएचओ भोपाल से जुड़े अधिकारियों के लिए आज राधाकृष्णन ऑडिटोरियम, मैनिट, भोपाल में भव्य संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मूल भाव 'आपकी बात, आपके साथ' रहा, जिसने इस आयोजन को अधिकारियों के विचारों, अनुभवों, समस्याओं और सुझावों के लिए एक सशक्त एवं सार्थक संवाद मंच में परिवर्तित कर दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भोपाल मॉड्यूल के उप महाप्रबंधक श्री साईं कृष्णा श्रीधरा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ, भोपाल सर्कल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं महासचिव श्री संजीव मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। विशेष अतिथि श्री सुनील राजवैद्य ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम का आत्मीय स्वागत भोपाल मॉड्यूल के अध्यक्ष श्री क्षितिज तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने अतिथियों एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति उसके सदस्यों के विश्वास, सहभागिता और एकजुटता में निहित है। उन्होंने कहा कि भोपाल मॉड्यूल अधिकारियों के हितों एवं उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भोपाल मॉड्यूल के उप महासचिव श्री सुबीन सिन्हा ने सम्मेलन को संबोधित



करते हुए कहा कि 'आपकी बात, आपके साथ' केवल सम्मेलन की विषय-वस्तु नहीं, बल्कि संगठन की कार्यशैली का मूल भाव है। प्रत्येक अधिकारी की समस्या, सुझाव और अपेक्षा संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खुला संवाद, आपसी विश्वास और सामूहिक सहभागिता ही संगठन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाती है। उन्होंने सभी अधिकारियों से संगठन के साथ मजबूती से जुड़े रहने और अपनी बात निर्भीकता से रखने का आह्वान किया। सम्मेलन में आरबीओ-1, आरबीओ-2 एवं आरबीओ-9 तथा एलएचओ भोपाल से आए अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अधिकारियों को अपनी समस्याएं, अनुभव एवं सुझाव खुलकर रखने का अवसर मिला। विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा एवं विचार-विमर्श हुआ तथा अधिकारियों की अपेक्षाओं और कार्यस्थल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संगठन के समक्ष रखा गया। इस अवसर पर एआईबीओसी मध्यप्रदेश के सचिव श्री दिनेश झा, ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुकेश सोनी, महासचिव श्री शोभित वाडेल, अधिकारी साख समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू मीणा सहित सर्कल एवं मॉड्यूल के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान संगठन की मूल भावना 'एकता ज़ संघर्ष ज़ समर्पण' पूरे आयोजन में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह ने सम्मेलन को एक यादगार आयोजन बना दिया।यह सम्मेलन महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि अधिकारियों और संगठन के बीच संवाद, विश्वास एवं सहभागिता को और मजबूत करने वाला प्रभावी मंच साबित हुआ। सम्मेलन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि संगठन तभी मजबूत होता है, जब प्रत्येक सदस्य अपनी बात रखता है और संगठन उस बात को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाता है। 'सदस्य की आवाज़ ही संगठन की ताकत है,और संगठन की एकजुटता ही अधिकारों की सबसे बड़ी शक्ति है।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **अमित शर्मा** द्वारा प्रकाशन स्थल बी-9 विवेक विहार कॉलोनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474001 से प्रकाशित एवं सर्वोदय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, नया बाजार केनरा बैंक के पास ग्वालियर (म.प्र.)-474001 से मुद्रित। स्थानीय संपादक राजीव शुक्ल* पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI - MPHIN/2019/79098/ E-mail: EKSATBULLETIN@GMAIL.COM, WWW.EKSATBULLETIN.IN, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088